नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बिहार से प्रसारित

सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHI/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 03, अंक 333, नई दिल्ली, रविवार 01 फरवरी 2026, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

सहनशील होना अच्छी बात है.. पर अन्याय का विरोध करना उससे भी उत्तम है..!!

03 भगवान शिव द्वारा बनाए गए कर्म के 7 सिद्धांत.
06 एक सीमित दुनिया से असीमित कल्पना तक: बाल-पठन संस्कृति का संकट
08 रांची पुलिस ने मादक पदार्थ सहित पांच को किया गिरफ्तार

दिल्ली परिवहन निगम के अनुबंध कर्मचारियों को स्थायी करने हेतु लगाई गुहार

25 हजार कर्मचारियों की पुकार: समान काम, समान वेतन का संवैधानिक अधिकार

संजय कुमार बाठला

दिल्ली की सड़कों पर रोजाना 40 लाख यात्रियों को सुरक्षित पहुंचाने वाली दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की बसों के पहिए अनुबंध कर्मचारियों के कंधों पर ही चल रहे हैं।

यह 25 हजार से अधिक संविदा/आउटसोर्स ड्राइवर व कंडक्टर, जिनमें से कई डीटीसी को पिछले 18 वर्षों से सेवा दे रहे हैं, आज भी स्थायीकरण की बाट जोह रहे हैं।

दिल्ली सड़क परिवहन अधिनियम, 1950 के तहत गठित इस निगम पर पूरी तरह निर्भर ये कर्मचारी समान काम के बदले समान वेतन, चिकित्सा सुविधा, यात्रा भत्ता और नौकरी की सुरक्षा से वंचित हैं।

क्या यह संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), 16 (सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर) और 21 (गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार) का उल्लंघन नहीं?

डीटीसी के ये कर्मचारी महामारी, प्रदूषण और यातायात जाम के बीच दिल्ली की 40 लाख जनता को सेवा दे रहे हैं, फिर भी उनकी दशा दयनीय है।

रोहिणी सेक्टर - 37 के विकास ड्राइवर आईडी 448 को ड्यूटी के दौरान निर्मम हत्या कर दी गई, लेकिन उसके परिवार को अभी तक उचित सहायता नहीं मिली।

इसी तरह, ड्राइवर पंकज को बिना कारण विभाग से हटाया गया।

कर्मचारी मात्र 862 रुपये प्रतिदिन पर काम करने को मजबूर हैं — ना टीए, ना डीए, ना चिकित्सा सुविधा।

क्या दिल्ली सरकार और DTC प्रबंधन इनकी पीड़ा अनसुनी करेगा?

* कानूनी आधार और नीतिगत मांगें:

* स्थायीकरण ही एकमात्र समाधान

* सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों जैसे उमर कांथ बनाम भारत सरकार (2008) और राजस्थान राज्य बनाम सर्वश्री गुजराज (1997) में स्पष्ट है कि लंबे समय से सेवा दे रहे अनुबंध कर्मचारियों को वरिष्ठता के आधार पर नियमित किया जाना चाहिए।

*** डीटीसी प्रबंधन को निम्न निर्देश जारी करने होंगे:**

* वरिष्ठता आधारित स्थायीकरण: सभी 25 हजार अनुबंध कर्मचारियों को तत्काल नियमित करें, ताकि आर्थिक सुरक्षा मिले।

* बीमा कवरेज: सभी ड्राइवर व कंडक्टरों के लिए 75 लाख रुपये का समग्र बीमा सुनिश्चित करें।

* मुआवजा और पुनर्वास: रोहिणी हत्याकांड के शिकार ड्राइवर के परिवार को 50 लाख रुपये की तत्काल सहायता दें;

* पंकज को सेवा में बहाल करें।

* सुविधाओं का विस्तार: समान वेतन, टीए/डीए, चिकित्सा और पेंशन लाभ प्रदान करें।

* ये मांगें केवल कर्मचारियों की नहीं, बल्कि दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की हैं।

* अस्थायी कर्मचारियों से बसें चलवाना सुरक्षा जोखिम बढ़ाता है — हाल के हादसों इसका प्रमाण हैं।

* दिल्ली सरकार को 10 हजार नई बसें तत्काल लानी चाहिए, जिसमें स्थायी कर्मचारी ही तैनात हों।

* यूनियनों और जनता से अपील: एकजुट होकर न्याय की लड़ाई लड़ें

* सभी DTC यूनियनों से हाथ जोड़कर अनुरोध है — कर्मचारियों की इस पुकार को मजबूती दें।

* भाइयों - बहनों, अपनी व्यथा फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर (X) और मीडिया चैनलों पर शेयर करें।

* भारत के सभी मंत्रियों, विधायकों और सांसदों को ईमेल भेजें।

हमें भारत के संविधान पर पूर्ण विश्वास है — हमें हमारा अधिकार अवश्य मिलेगा

डीटीसी ना केवल परिवहन का स्तंभ है, बल्कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण का आधार भी:- सरकार से अपेक्षा है कि यह ऐतिहासिक कदम उठाए, वरना सार्वजनिक हित में न्यायिक पीआईएल दायर करने का समय आ गया है।

कर्मचारी की यह पुकार अनसुनी न रहे — न्याय की घड़ी अब बज चुकी है। — संपादकीय टिप्पणी

टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत

आरडब्ल्यूए एडवाइजरी - वाहन सुरक्षा

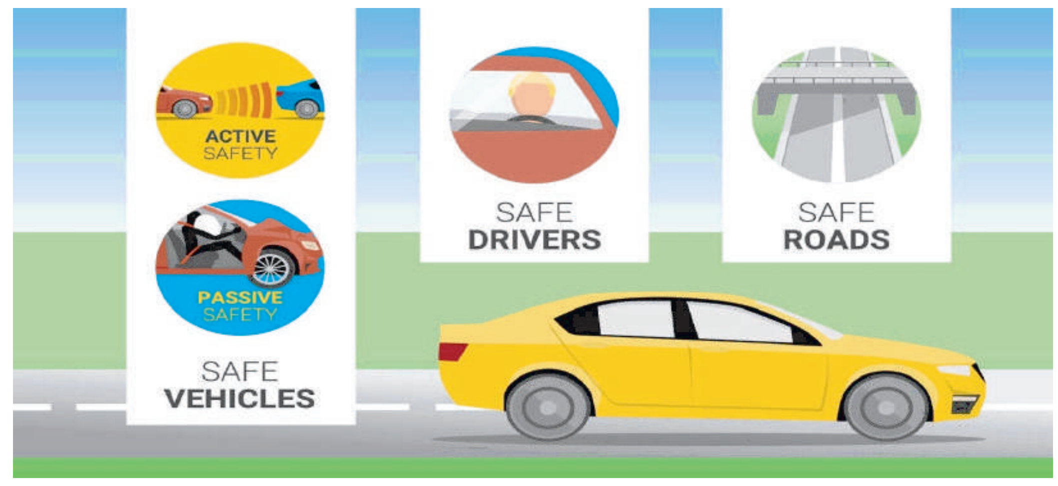

परिवहन विशेष न्यूज

एसआई अनूप राणा, आई/सी पीपी हरी नगर

आपकी गाड़ी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी निवासियों से अनुरोध है कि वाहन पार्क करते समय निम्न सावधानियाँ अपनाएँ

* टायर क्लैम्प लगाकर पार्क करें

* गाड़ी को कवर से ढककर खड़ा करें

* गियर लॉक / हैंडल लॉक अवश्य लगाएँ

* अपनी गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर इंस्टॉल कराएँ

* मोटरसाइकिल व कार में स्पूफिंग डिवाइस लगवाएँ

* अपनी गाड़ी में एयर टैग (Air Tag) इंस्टॉल करें

आपकी सतर्कता ही आपकी सुरक्षा है

सहयोग के लिए धन्यवाद,

एसआई अनूप राणा, आई/सी पीपी हरी नगर

परिवहन विशेष जनहित विशेष कॉलम

Parle-G फैक्ट्री बंद : एक युग का अंत, जानिए पूरी कहानी

पिंकी कुंडू

भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा, जहां कभी Parle-G बिस्किट न खाया गया हो। चाय के साथ डुबोकर खाया जाने वाला यह बिस्किट सिर्फ एक खाद्य पदार्थ नहीं, बल्कि पीढ़ियों की भावनाओं से जुड़ा हुआ नाम बन चुका है। लेकिन अब इसी Parle-G से जुड़ी एक ऐतिहासिक खबर सामने आई है, जिसने लोगों को भावुक कर दिया है।

मुंबई के विले पार्ले स्थित Parle-G की ऐतिहासिक फैक्ट्री अब बंद हो चुकी है। यह वही फैक्ट्री है, जहां से भारत के सबसे लोकप्रिय बिस्किट ने अपनी पहचान बनाई थी। साल 1929 में स्थापित यह फैक्ट्री अब एक नए व्यावसायिक प्रोजेक्ट में तब्दील होने जा रही है।

1929 से शुरू हुआ था Parle-G का सफर

Parle Products की स्थापना 1929 में मोहनलाल दयाल चौहान ने मुंबई के विले पार्ले इलाके में की थी। शुरुआत में यहां टॉफी और कैंडी बनाई जाती थीं, लेकिन साल 1939 में कंपनी ने बिस्किट निर्माण की ओर कदम बढ़ाया। यहीं से जन्म हुआ Parle-G का, जिसने धीरे-धीरे देश के हर घर में अपनी जगह बना ली।

दिलचस्प बात यह है कि “Parle” नाम भी इसी इलाके से जुड़ा है, जिसे Padle और Irle गांवों या फिर विरलेश्वर और पारलेश्वर मंदिरों से जोड़ा जाता है।

Parle-G की पैकेट वाली लड़की का सच

Parle-G के पैकेट पर बनी मासूम बच्ची को लेकर दशकों से रहस्य बना हुआ था। कई लोग इसे सुधा मूर्ति, नीरू देशपांडे या किसी असली बच्ची से जोड़ते रहे। लेकिन Parle Products के वाइस प्रेसिडेंट ने स्पष्ट किया कि यह बच्ची असल में कोई वास्तविक व्यक्ति नहीं है।

यह चित्र 1960 के दशक में कलाकार मगनलाल दहिया द्वारा Everest Creative के लिए डिजाइन किया गया था। इसका उद्देश्य मासूमियत, शुद्धता और पारिवारिक भावनाओं को दर्शाना था। यही वजह है कि यह चेहरा दशकों तक लोगों के दिलों में बस गया।

2016 में बंद हुआ उत्पादन, अब होगा पुनर्विकास

Parle Products ने वर्ष 2016 के मध्य में इस फैक्ट्री में बिस्किट निर्माण बंद कर दिया था। अब 7 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (SEIAA) ने इस भूमि के पुनर्विकास को मंजूरी दे दी है।

करीब 54,438.80 वर्ग मीटर (13.54 एकड़) क्षेत्र में फैली इस जमीन पर अब एक बड़ा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। इसके लिए 21 पुरानी इमारतों को गिराने की अनुमति दी गई है।

यह फैसला न केवल औद्योगिक दृष्टि से अहम है, बल्कि भावनात्मक रूप से भी लोगों को झकझोरने वाला है।

Parle सिर्फ बिस्किट नहीं, एक विरासत है

Parle-G के अलावा कंपनी ने Hide & Seek, Krackjack, Monaco जैसे लोकप्रिय बिस्किट भी बनाए। साथ ही Kismi, Melody, Eclairs, Mazelo जैसी टॉफियां और स्नैक्स, रस्क, केक व ब्रेकफास्ट सीरियल्स भी बाजार में उतारे।

हालांकि वक्त के साथ बाजार बदला, प्रतिस्पर्धा बढ़ी, लेकिन Parle-G की लोकप्रियता कभी कम नहीं हुई।

यादों में हमेशा जिंदा रहेगा Parle-G

भले ही विले पार्ले की फैक्ट्री अब इतिहास बन गई हो, लेकिन Parle-G की खुशबू, स्वाद और उससे जुड़ी यादें कभी खत्म नहीं होंगी। यह सिर्फ एक बिस्किट नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के बचपन का हिस्सा है।

\चाहे आने वाले समय में बाजार कितना भी बदल जाए, Parle-G हमेशा दिलों में अपनी जगह बनाए रखेगा।

भुवनेश्वर में सुभद्रा बस सेवा शुरू की जाएगी: मंत्री कृष्णा महापात्र

मनोरंजन शासमल, स्टेट हेड ओड़िशा

भूबनेश्वर : हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर कृष्ण चंद्र महापात्रा ने राजधानी में महिला यात्रियों के लिए एक बड़ी मदद की घोषणा की है।हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर कृष्ण चंद्र महापात्रा ने शनिवार को कहा कि महिलाओं की सेफ्टी और मोबिलिटी बढ़ाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, ओडिशा सरकार भुवनेश्वर में सुभद्रा बस सर्विस शुरू करने जा रही है।उन्होंने कहा कि महिला पैसेंजर के लिए खास तौर पर बनाई गई इस सर्विस को महिला ड्राइवर चलाएंगी। यह पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जेंडर एम्पावरमेंट की दिशा में एक ज़रूरी कदम है।

मीडिया वालों से बात करते हुए, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर ने कहा कि बसें महिलाओं की सेफ्टी और आराम को प्रायोरिटी देंगी। 'सुभद्रा बस' महिलाओं के लिए एक डेडिकेटेड सर्विस होगी। इसे ट्रेंड महिला ड्राइवर चलाएंगी। उन्होंने कहा कि यह ज़्यादा सेफ और ज़्यादा इनक्लूसिव अर्बन ट्रांसपोर्ट बनाने की दिशा में एक कदम है।

भुवनेश्वर से चुनी गई महिला ड्राइवरों ने पुणे में गाड़ियां संभालने और पैसेंजर सेफ्टी प्रोटोकॉल बनाए रखने की ट्रेनिंग ली है। बसों में मॉडर्न सेफ्टी फीचर्स, CCTV और इमरजेंसी सिस्टम लगे होंगे ताकि सफर का अनुभव सेफ रहे।

टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत

https://tolwa.com/about.html | tolwaindia@gmail.com
tolwadelhi@gmail.com

पिंकी कुंडू

आज का साइबर सुरक्षा विचार : स्टैनली एक नया, अत्यधिक भ्रामक ब्राउज़र मैलवेयर टूलकिट है जो नकली वेबसाइट दिखाता है जबकि एड्रेस बार में असली URL दिखाई देता रहता है।

स्टैनली से बचाव और इसे हटाने के लिए उपयोगकर्ताओं को सक्रिय ब्राउज़र स्वच्छता (जैसे हानिकारक एक्सटेंशन से बचना, सॉफ़्टवेयर को अपडेट रखना) के साथ-साथ मज़बूत एंडपॉइंट सुरक्षा और घटना-प्रतिक्रिया उपायों को अपनाना चाहिए। तुरंत अपने ब्राउज़र एक्सटेंशन की जाँच करें और संदिग्ध को हटाएँ।

स्टैनली कैसे काम करता है

- मैलवेयर-एज़-ए-सर्विस टूलकिट: रूसी फ़ोरम पर $2,000–$6,000 में बेचा जा रहा है।

- स्पूफिंग तकनीक: यह iframe overlays और एलिमेंट इंजेक्शन का उपयोग करके नकली वेबसाइट दिखाता है, जबकि ब्राउज़र का एड्रेस बार असली डोमेन दिखाता रहता है।

* **वितरण:** अक्सर Chrome एक्सटेंशन के रूप में आता है, कुछ पर गूगल का “Featured” बैज भी होता है।

- **क्षमताएँ:** लॉगिन क्रेडेंशियल चोरी, पुश नोटिफिकेशन, बैकअप डोमेन रोटेशन, और लगातार कमांड-एंड-कंट्रोल सर्वर से संपर्क।

बचाव के उपाय

1. ब्राउज़र और एक्सटेंशन की सुरक्षा

o केवल भरोसेमंद डेवलपर्स के एक्सटेंशन इंस्टॉल करें।

o समय-समय पर एक्सटेंशन की जाँच करें और अनावश्यक को हटाएँ।

o एंटरप्राइज़ वातावरण में ऑटोमैटिक इंस्टॉलेशन रोकें।

2. सॉफ़्टवेयर अपडेट

- Chrome, Edge, Firefox और अन्य ब्राउज़र को हमेशा नवीनतम संस्करण में रखें।

- ऑपरेटिंग सिस्टम के सुरक्षा पैच समय पर लागू करें।

3. एंडपॉइंट सुरक्षा

- एंटी-मैलवेयर सॉफ़्टवेयर का उपयोग करें जिसमें रियल-टाइम ब्राउज़र प्रोटेक्शन हो।

- Behavioral detection सक्षम करें ताकि असामान्य गतिविधियों को पकड़ा जा सके।

4. नेटवर्क और पॉलिसी नियंत्रण

- DNS फ़िल्टरिंग और वेब प्रॉक्सी का उपयोग करें ताकि संदिग्ध डोमेन ब्लॉक हों।

- संवेदनशील लॉगिन के लिए Zero Trust policies लागू करें (जैसे मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन)।

5. उपयोगकर्ता जागरूकता

- उपयोगकर्ताओं को संदिग्ध लॉगिन पेज पहचानने की ट्रेनिंग दें।

- केवल URL बार पर भरोसा न करें, बल्कि HTTPS सर्टिफिकेट विवरण भी जाँचें।

हटाने के उपाय (संक्रमित होने पर)

1. संदिग्ध एक्सटेंशन हटाएँ

- ब्राउज़र सेटिंग्स → एक्सटेंशन → संदिग्ध ऐड-ऑन हटाएँ।

- ब्राउज़र को डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पर रीसेट करें।

2. सुरक्षा स्कैन चलाएँ

- अपडेटेड एंटी-मैलवेयर टूल (जैसे Malwarebytes, Microsoft Defender) से पूरा स्कैन करें।

- पाए गए खतरों को क्वारंटीन और डिलीट करें।

3. ब्राउज़र डेटा साफ़ करें

- कुकीज़, कैश और सेव किए गए पासवर्ड हटाएँ।

- ब्राउज़र में सेव किए गए पासवर्ड रद्द करें।

4. सिस्टम की जाँच करें

- स्टार्टअप प्रोग्राम और शेड्यूल्ड टास्क देखें।

- Autoruns (Sysinternals) जैसे टूल से छिपी हुई एंट्री खोजें।

5. पासवर्ड बदलें

- संक्रमण के दौरान उपयोग किए गए सभी पासवर्ड तुरंत बदलें।

- वित्तीय और ईमेल खातों पर मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन सक्षम करें।

स्वास्थ्य विशेष

स्वास्थ्य आपका कोशिश हमारी

लिवर पर बुरी आदतों का असर

पिंकी कुंडू

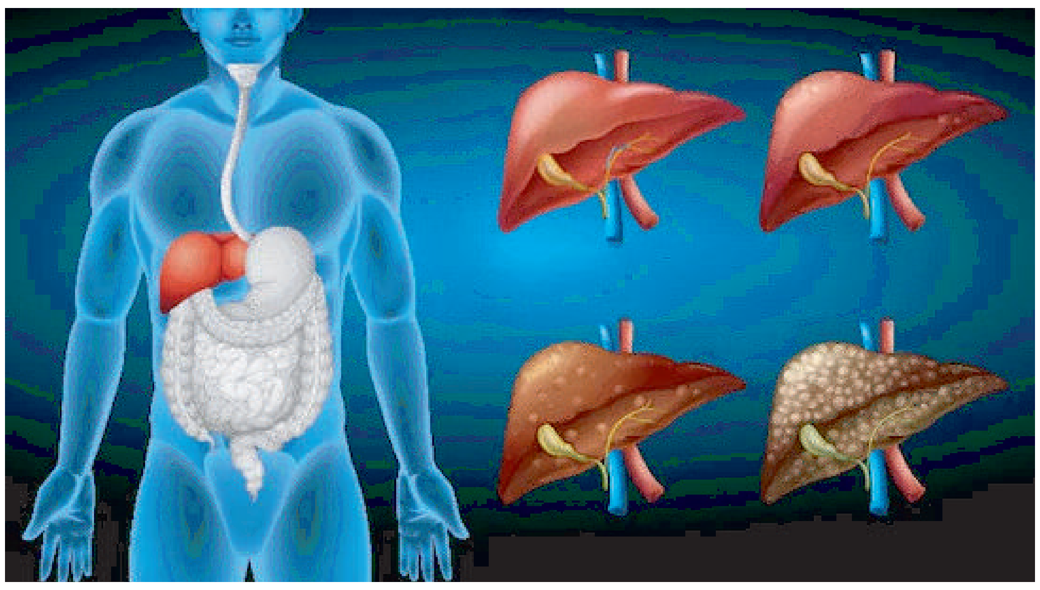

हम हमेशा सुनते हैं कि "हेल्थ ही वेल्थ है" लेकिन इस भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल में, सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज़ की जाने वाली चीज़ हमारी अपनी हेल्थ है।

हर चीज़ के लिए टाइम होता है लेकिन शरीर के लिए नहीं! इसी का असर लिवर पर पड़ता है, जो एक बहुत ज़रूरी अंग है।

लिवर – शरीर का साइलेंट हीरो

1. शरीर में 500 से ज़्यादा प्रोसेस में लिवर का रोल
2. खाना पचाना और एनर्जी बनाना
3. खून को साफ़ रखना
4. ज़हरीले एलिमेंट्स को निकालना
5. हेल्दी मेटाबॉलिज़्म बनाए रखना

अगर लिवर फेल हो जाए, तो पूरा शरीर खराब हो जाता है।

लिवर खराब होने के मुख्य कारण

1. जंक फ़ूड / प्रोसेस्ड फ़ूड
2. एक्सरसाइज़ की कमी
3. बहुत ज़्यादा शराब पीना
4. फ़ैटी और भारी खाना
5. लंबे समय तक ड्रग्स लेना
6. गंदा पानी और खाना
7. शरीर में दिखने वाले लक्षणों को नज़रअंदाज़ करना

लिवर से जुड़ी आम चेतावनियाँ (लक्षण)

1. स्किन और आँखों का पीला पड़ना
2. पेट या पैरों में सूजन
3. उल्टी, भूख न लगना
4. चक्कर आना, खुजली
5. बहुत पीला यूरिन
6. स्टूल में खून

अगर आपको ये लक्षण दिखें, तो देर न करें!

लिवर की बड़ी बीमारियाँ

1. हेपेटाइटिस / पीलिया, टाइपः A, B, C, D, E

* A और E – गंदा पानी/खाना
* B, C, D – इन्फेक्टेड खून/फ्लूइड के संपर्क में आने से
* हेपेटाइटिस A और B के लिए वैक्सीन उपलब्ध है
* हेपेटाइटिस C और E के लिए कोई वैक्सीन नहीं है

अगर नज़रअंदाज़ किया जाए, लिवर सिरोसिस / कैंसर का खतरा

2. लिवर सिरोसिस

* लिवर को हमेशा के लिए नुकसान
* लिवर सिकुड़ जाता है, सख्त हो जाता है
* सेल्स खत्म हो जाते हैं और रेशेदार चीज़ें बढ़ने लगती हैं

*** मुख्य कारणः**

* ज़्यादा शराब पीना
* गलत डाइट
* बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल
* कुछ दवाओं के साइड इफ़ेक्ट

गंभीर मामलों में लिवर ट्रांसप्लांट ही एकमात्र उपाय है

3. लिवर कैंसर

* लिवर सेल्स खत्म हो जाते हैं
* सिरोसिस, फैटी लिवर, जॉन्डिस से खतरा बढ़ जाता है
* इलाजः
* सर्जरी
* कीमोथेरेपी
* रेडिएशन
* ज़रूरत पड़ने पर ट्रांसप्लांट

जॉन्डिस – नज़रअंदाज़ न करें!

* गंदे पानी से होने वाली बीमारी
* बिलीरुबिन बढ़ने से आँखें पीली दिखती हैं
* यह सही दवा + डाइट से ठीक हो जाता है
* नज़रअंदाज़ करने पर यह जानलेवा हो सकता है

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सिर्फ़ हेल्दी शरीर से ही मिल सकते हैं।

जब मैं मरीजों से खान पान और दिनचर्या सुधारने की बात करती हूँ, तो बहुतों का जवाब बड़ा कैजुअल होता है

अरे डॉक्टर साहब, हद से हद क्या होगा, मर ही तो जाएंगे।

डॉ विजाता आर्या

जब मैं मरीजों से खान पान और दिनचर्या सुधारने की बात करती हूँ, तो बहुतों का जवाब बड़ा कैजुअल होता है।

अरे डॉक्टर साहब, हद से हद क्या होगा, मर ही तो जाएंगे।

मेरा जवाब भी सीधा होता है।

आप इतने गरीब नहीं हैं कि आपका इलाज न हो। परिवार वाले घर बेचकर इलाज कराएंगे। और विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है कि आपको इतनी आसानी से मरने भी नहीं देगा। हर अंग में सुई, पाइप और मशीन लगाकर आपको जिंदा रखा जाएगा।

यहीं से असली सवाल शुरू होता है।

मामला सिर्फ जिंदा रहने का नहीं है।

यहीं HALY की बात आती है।

HALY का मतलब है Health Adjusted Life Years।

यानि आपने कितने साल जिए, यह नहीं। आपने कितने साल स्वस्थ होकर जिए, यह।

मान लीजिए कोई व्यक्ति 70 साल जिया। लेकिन उसमें से 15 साल शुगर, ब्लड प्रेशर, किडनी, सांस, घुटनों के दर्द, डिप्रेशन और दवाइयों के सहारे गुजरे। ICU, अस्पताल, बार बार भर्ती, दूसरों पर निर्भर रहना। तो कागज पर उसकी उम्र 70 साल है, लेकिन HALY के हिसाब से उसके स्वस्थ जीवन के साल बहुत कम हो गए।

आधुनिक चिकित्सा आज मौत को टालना जानती है।

लेकिन बीमारी के साथ लंबा जीवन देना भी जानती है।

डायलिसिस, स्टेंट, पेसमेकर, इंसुलिन, वेंटिलेटर। सब कुछ उपलब्ध है। सवाल यह नहीं है कि आप बचेंगे या नहीं। सवाल यह है कि किस हालत में बचेंगे।

HALY यही बताता है कि खराब खान पान, गलत दिनचर्या और लगातार अनदेखी से आप जल्दी नहीं मरते। आप धीरे धीरे बीमार होकर जिंदा रहते हैं। और यही सबसे महंगा और सबसे पीड़ादायक जीवन होता है।

आयुर्वेद सदियों से जो बात कहता आया है, HALY उसी को आधुनिक भाषा में मापता है।

दीर्घायु नहीं, स्वस्थायु।

ऐसी उम्र जहां व्यक्ति चल सके, सोच सके, काम कर सके, अपने फैसले खुद ले सके। मशीनों के भरोसे नहीं, शरीर के भरोसे जिए।

इसलिए जब मैं खान पान सुधारने और दिनचर्या बदलने की बात करती हूँ, तो वह आपको मौत से बचाने के लिए नहीं होती। वह आपकी HALY बढ़ाने के लिए होती है।

ताकि आप जिंदा भर नहीं रहें, बल्कि जीवन भी जी सकें।

क्योंकि अंत में सवाल यह नहीं होता कि आदमी कब मरा।

सवाल यह होता है कि मरने से पहले वह किस हालत में जिया।

कॉफी नहीं, ये है थायरॉइड में सही प्री-वर्कआउट आइडियाज

केले को एक बेहतरीन प्री-वर्कआउट के रूप में देखा जाता है। आप आधा केला या फिर एक छोटा केला लें और ऊपर से एक चुटकी दालचीनी डालकर खा लें। इससे आपको तुरंत एनर्जी मिलेगी और मसल्स में क्रैम्प कम होंगे। साथ ही, वर्कआउट में ताकत बनी रहती है।

फिट रहने के लिए हर किसी को वर्कआउट करने की सलाह दी जाती है, लेकिन अगर आपको थायरॉइड हो तो ऐसे में वर्कआउट करना काफी चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि एक्सरसाइज करने का मन तो करता है, लेकिन शरीर साथ नहीं देता। वर्कआउट करते हुए जल्दी थकान महसूस होती है या फिर कभी चक्कर-सा महसूस होता है, जिसकी वजह से सही तरह से एक्सरसाइज करना संभव ही नहीं हो पाता है।

अमूमन लोग एनर्जी के लिए वर्कआउट से पहले कॉफी या रेडीमेड प्री-वर्कआउट ड्रिंक का सेवन करते हैं। लेकिन अगर आपको थायरॉइड है तो ऐसे में इससे शरीर पर उल्टा असर पड़ सकता है। थायरॉइड में जरा-सी लापरवाही थकान, सूजन और वजन बढ़ने की वजह बन सकती है। इसलिए, आपको सही प्री-वर्कआउट चुनने की जरूरत होती है। तो चलिए आज इस लेख में हम इस बारे में विस्तार से जानेंगे-

भीगा हुआ बादाम और किशमिश

वर्कआउट से करीबन आधे घंटे पहले आप 4-5 भीगे बादाम और 4-5 किशमिश ले सकती हैं। बादाम से हेल्दी फैट और हल्का प्रोटीन मिलता है, जबकि किशमिश से नेचुरल एनर्जी देती है। जिससे आपको थकान कम होती है। थायरॉइड में इसे एक अच्छा प्री-वर्कआउट माना जाता है, क्योंकि इसमें कोई स्टिमुलेंट नहीं होता है और ब्लड शुगर धीरे-धीरे बढ़ती है।

केला और दालचीनी

केले को एक बेहतरीन प्री-वर्कआउट के रूप में देखा जाता है। आप आधा केला या फिर एक छोटा केला लें और ऊपर से एक चुटकी दालचीनी डालकर खा लें। इससे आपको तुरंत एनर्जी मिलेगी और मसल्स में क्रैम्प कम होंगे। साथ ही, वर्कआउट में ताकत बनी रहती है।

भुना चना और थोड़ा गुड़

वर्कआउट से पहले आप एक मुट्ठी भुना चने के साथ छोटा सा गुड़ का टुकड़ा भी ले सकती हैं। इससे आपको अच्छी एनर्जी और प्रोटीन मिलता है। साथ ही, वर्कआउट के दौरान स्टैमिना बना रहता है और भूख कंट्रोल होती है। थायरॉइड में इसे सेफ माना जाता है, क्योंकि इसमें प्रोसेस्ड शुगर नहीं होती है और लंबे समय तक एनर्जी बनी रहती है। यह आपके मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट भी करता है।

नारियल पानी

अगर आप चाहें तो वर्कआउट से करीबन 20 मिनट पहले एक गिलास सादा नारियल पानी भी ले सकते हैं। इससे शरीर हाइड्रेट रहता है और कमजोरी और चक्कर की शिकायत नहीं होती है। नारियल पानी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखने में मदद करता है।

हमारे दिल से जो खून पंप होता है, उसका तक़रीबन 6 से 11 फ़ीसद हिस्सा हमारी हड्डियों तक जाता है, ताकि उनमें मौजूद ज़िंदा ख़लिये ज़िंदा रह सकें।

पिंकी कुंडू

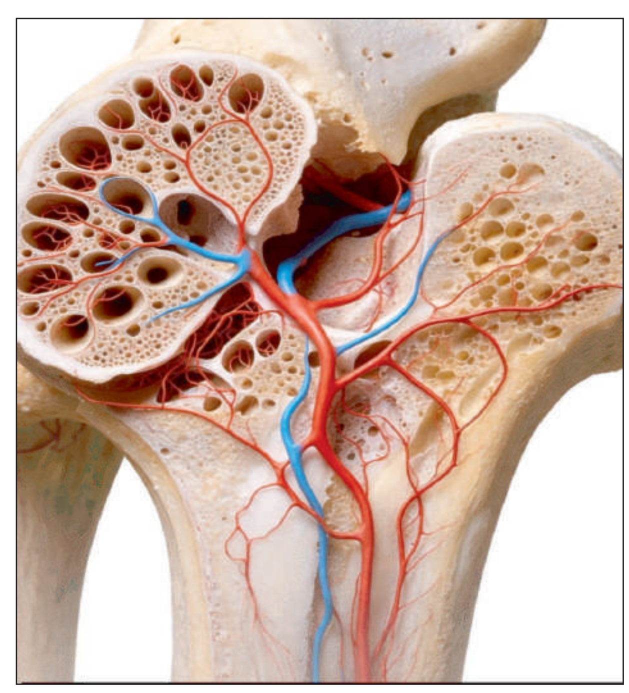

हड्डियों की सतह पर छोटे - छोटे सुराख़ होते हैं, इन्हीं सुराख़ों से खून की नालियाँ हड्डी के अंदर दाख़िल होती हैं, फिर हड्डी के अंदर मौजूद रास्तों यानी कैनाल्स से गुज़रते हुए हड्डी के गूदे (बोन मैरो) तक पहुँचती हैं।

यही खून हड्डी के गूदे को ग़िज़ा देता है, और वहीं से नए खून के ख़लिये, प्लेटलेट्स वग़ैरह तैयार होकर पूरे जिस्म में भेजे जाते हैं।

एक वैस्कुलर कास्ट तजुर्बा किया गया, जिसमें मुर्ग़ी की हड्डी की खून की नालियों को एक ख़ास तरीक़े से नुमायाँ किया गया।

इस तजुर्बे से यह बात सामने आई कि हड्डियों के सिरों पर खून की नालियाँ ज़्यादा होती हैं, जो जोड़ों की मज़बूती और हड्डियों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं।

आख़िर में एक सादा ख़ाका भी दिखाया गया है, जिसमें साफ़ नज़र आता है कि हड्डी के सख़्त खोल के अंदर खून की नालियाँ और नसें किस तरह फैली होती हैं।

इससे यह हक़ीक़त सामने आती है कि हड्डियाँ भी ज़िंदा होती हैं, उन्हें भी खून की ज़रूरत होती है।

मासिक धर्मः अब स्वास्थ्य नहीं, संवैधानिक सम्मान का प्रश्न

प्रो. आरके जैन "अरिजीत"

भारतीय लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के इतिहास में एक निर्णायक और साहसिक मोड़ तब आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी 2026 को यह स्पष्ट किया कि मासिक धर्म स्वास्थ्य केवल एक जैविक प्रक्रिया या साधारण स्वास्थ्य सुविधा नहीं, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के मौलिक अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। यह फैसला सदियों से मासिक धर्म के नाम पर समाज में फैलाई गई चुप्पी, शर्म और उपेक्षा की जड़ पर सीधा प्रहार करता है। अब यह स्वीकार किया गया है कि मासिक धर्म से जुड़ी असुविधा, अपमान और संसाधनों का अभाव किसी भी लड़की की शिक्षा, गरिमा और भविष्य को सीमित नहीं कर सकता। यह निर्णय न्यायपालिका की मानवीय संवेदनशीलता और सामाजिक यथार्थ की गहरी समझ का सशक्त प्रमाण है।

यह फैसला केवल स्वास्थ्य से जुड़ा आदेश नहीं, बल्कि समानता और गरिमा की संवैधानिक घोषणा है। न्यायालय ने मासिक धर्म को स्वास्थ्य की सीमित परिभाषा से बाहर निकालते हुए उसे समानता, गोपनीयता, गरिमा और शिक्षा के अधिकार से जोड़ा। न्यायाधीशों ने स्पष्ट कहा कि यदि किसी लड़की को सिर्फ इसलिए स्कूल छोड़ना पड़े क्योंकि उसके पास सुरक्षित पैड या स्वच्छ शौचालय नहीं है, तो यह संविधान की आत्मा पर सीधा आघात है। "एक पीरियड वाक्य का अंत होना चाहिए, किसी लड़की की शिक्षा का नहीं" जैसी टिप्पणी ने इस निर्णय को गहरी मानवीय संवेदना दी और उन लाखों छात्राओं की पीड़ा को आवाज दी, जो हर महीने खामोशी से शिक्षा से दूर हो जाती थीं।

न्यायालय ने इस निर्णय को केवल आदर्शों की घोषणा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे जमीन पर उतारने के लिए स्पष्ट और व्यावहारिक निर्देश दिए। कक्षा 6 से 12 तक की सभी छात्राओं को मुफ्त, उच्च गुणवत्ता वाले ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया। इन पैड्स का एएसटीएम डी-6954 जैसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होना अनिवार्य किया गया, ताकि स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित हो सके। साथ ही, पैड्स की सहज, सुरक्षित और गोपनीय उपलब्धता के लिए स्कूलों में वेंडिंग मशीन या नामित अधिकारी की व्यवस्था तय की गई, जिससे छात्राओं की झिझक और असहजता पूरी तरह दूर की जा सके।

इसके साथ ही स्कूलों में "मासिक धर्म स्वास्थ्य प्रबंधन कॉर्नर" स्थापित करने का आदेश दिया गया, जहाँ अतिरिक्त यूनिफॉर्म, स्पेयर इनरवियर, डिस्पोजेबल बैग और आवश्यक स्वच्छता सामग्री उपलब्ध होगी। दिव्यांग छात्राओं के लिए व्हीलचेयर-अनुकूल शौचालय और सहायक उपकरण जैसी विशेष सुविधाएँ अनिवार्य की गईं। निजी स्कूलों द्वारा निर्देशों की अवहेलना पर मान्यता रद्द करने का प्रावधान रखकर जवाबदेही को मजबूत किया गया, ताकि यह फैसला केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि हर छात्रा के जीवन में वास्तविक बदलाव ला सके।

यह निर्णय केवल सुविधाएँ उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज की जड़ जमाई सोच को बदलने की सशक्त पहल है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मासिक धर्म स्वास्थ्य किसी एक वर्ग या केवल लड़कियों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। स्कूलों में लड़कों और लड़कियों दोनों को वैज्ञानिक और तथ्यात्मक जानकारी देने पर जोर देकर शर्म, डर और मिथकों की दीवार तोड़ने का संदेश दिया गया। जब मासिक धर्म को सामान्य और प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाएगा, तभी वास्तविक समानता और सम्मान संभव हो पाएगा। यह फैसला चुप्पी और संकोच की संस्कृति को खुले संवाद और समझ की संस्कृति में बदलने का आह्वान करता है।

इस फैसले के केंद्र में शिक्षा के अधिकार को रखा गया है। न्यायालय ने शिक्षा को "मल्टीप्लायर राइट" मानते हुए कहा कि यह अन्य सभी अधिकारों को सशक्त बनाती है। यदि मासिक धर्म के कारण किसी लड़की की पढ़ाई बाधित होती है, तो वह केवल स्कूल से दूर नहीं होती, बल्कि उसके भविष्य, आत्मनिर्भरता और सम्मान के अवसर भी छिन जाते हैं। इसी कारण आरटीई अधिनियम के तहत इन मानकों का पालन अनिवार्य किया गया और पाठ्यक्रम में मासिक धर्म जागरूकता को शामिल करने की सिफारिश की गई। यह कदम दीर्घकालिक और स्थायी सामाजिक परिवर्तन की मजबूत नींव रखेगा।

पर्यावरण संरक्षण को भी इस निर्णय में समान महत्व दिया गया है। प्लास्टिक आधारित पैड्स से होने वाले प्रदूषण और स्वास्थ्य जोखिमों को देखते हुए बायोडिग्रेडेबल विकल्प को अनिवार्य करना दूरदर्शी कदम है। इससे स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ प्रकृति के संरक्षण का संतुलन स्थापित होता है। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में, जहाँ स्वच्छता सुविधाएँ सबसे कमजोर हैं, यह फैसला विशेष रूप से परिवर्तनकारी सिद्ध होगा। पहले से चल रही योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर एकसमान और मजबूत ढांचा मिलने से क्षेत्रीय असमानताएँ कम होंगी और लाभ हर जरूरतमंद तक पहुँचेगा।

यह फैसला केवल आज की जरूरतों तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को आकार देने वाला है। बेहतर मासिक स्वास्थ्य से संक्रमण घटेंगे, आत्मविश्वास मजबूत होगा और लड़कियाँ बिना बाधा शिक्षा से जुड़ी रहेंगी। शिक्षित और स्वस्थ महिलाएँ परिवार, समाज और अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनती हैं। सरकारों से समयबद्ध अनुपालन रिपोर्ट मांगकर न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह निर्णय कागजों में सिमटने वाला नहीं, बल्कि जमीन पर उतरने वाला बदलाव है। यह फैसला सामाजिक न्याय, मानवीय गरिमा और संवैधानिक मूल्यों की सशक्त विजय है।

यह निर्णय हमें स्पष्ट रूप से याद दिलाता है कि संविधान केवल कानूनी प्रावधानों का संग्रह नहीं, बल्कि हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देने वाला जीवंत दस्तावेज है। मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार घोषित करना उस पुरानी सोच को सीधी और निर्णायक चुनौती है, जिसने इसे लंबे समय तक शर्म, चुप्पी और भेदभाव से जोड़कर रखा। अब यह अधिकार हर भारतीय बेटी का है, चाहे उसकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। समय आ गया है कि समाज, सरकार और संस्थाएँ मिलकर इस परिवर्तन को धरातल पर उतारें। यह फैसला केवल एक न्यायिक घोषणा नहीं, बल्कि गरिमा, समानता और साहस से भरे नए युग की मजबूत शुरुआत है।

भगवान शिव द्वारा बनाए गए कर्म के 7 सिद्धांत.

पिंकी कुंडू

शास्त्रो में भगवान शिव को सृष्टि के विनाशक के तौर पर दर्शाया गया है लेकिन साथ ही यह भी बताया गया है कि स्वयं शिव ही एक नया आरंभ कर सकते हैं।

महादेव द्वारा बताए गए कर्म के इन 7 सिद्धांतों का ध्यान रखने से व्यक्ति जीवन में आने वाली हर विपदा का सामना कर सकता है।

1. नहीं देना चाहिए झूठ का साथ इंसान पूरी जिंदगी ये सोचकर झूठ, कपट और धोखेबाजी का साथ देता है कि इससे कभी कोई हानि नहीं होगी। लेकिन भगवान शिव ने खुद कहा है कि अंत में इन सभी कर्मों की भरपाई करनी पड़ती है। झूठ और कपट के साथ केवल छोटी-मोटी लड़ाई ही जीता जा सकती हैं। लेकिन जीवन के बड़े युद्ध जीतने के लिए सत्य ही काम आता है। इसलिए हमेशा न्याय का साथ देना चाहिए।

2. कैसे करें ब्रह्म ज्ञान की खोज इस विश्व में हर व्यक्ति को पूरा ज्ञान नहीं है लेकिन सभी के पास किसी - न - किसी चीज का ज्ञान हैं। भगवान शिव के अनुसार, ब्रह्म ज्ञान की खोज के लिए हमें अपने भीतर ही उसकी तलाश करनी होगी। ये हमें कहीं बाहर से प्राप्त नहीं हो सकता।

3. क्या है भ्रम भोलेनाथ ने अपने कर्म के सिद्धांत में इस बात का वर्णन किया है कि यदि किसी व्यक्ति की खुशियां किसी भौतिक पदार्थ से जुड़ी है तो वह खुशी उस व्यक्ति के लिए एक भ्रम है। क्योंकि वह वस्तु नश्वर है जिसका अंत होना निश्चित है। इसलिए व्यक्ति को भौतिक आकर्षण से बचकर रहना चाहिए।

4. कहां ढूंढे वास्तविक खुशी व्यक्ति हर काम अपनी या अपने परिवार की खुशी के लिए करता है। वास्तविक खुशी को किसी सीमा में बांधकर नहीं रखा जा सकता। महादेव के अनुसार, खुशी मस्तिष्क की वह स्थिति है जब व्यक्ति आंतरिक रूप से संतुष्ट और प्रसन्न होता है। इसलिए खुशी की तलाश भी स्वयं के भीतर ही की जा सकती है, न की बाहर।

5. पानी से सीखें ये गुण भगवान शिव ने अपने कर्म के पांचवें सिद्धांत में कहा है कि व्यक्ति को पानी की तरह निराकार रहना चाहिए। पानी को किसी भी बर्तन में डाला जाए तो वह उसी का आकार ले लेता है। अगर व्यक्ति पानी के इस गुण को अपना लेता है तो वह अपने आप को किसी भी परिस्थिति के अनुसार ढाल सकता है। इससे आपकी खुशियां भी क्षणभंगुर नहीं होंगी।

6. कैसे करें इंद्रियों का प्रयोग जब व्यक्ति का मस्तिष्क शांत होता है, तो उसका हृदय, उसकी भावनाएं उसके नियंत्रण में होती हैं। इससे वह अपने मन की आवाज को अच्छे से सुन व समझ सकता है। जब व्यक्ति की इंद्रियां उसके वश में रहेंगी तभी वह उनका अपने अनुसार प्रयोग कर पाएगा।

* भगवान शिव द्वारा बताया गया सातवां कर्म का यह आखिरी सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण हैं।

7. मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य उसी परम सत्ता में विलीन हो जाना है जहां से उसकी उत्पत्ति हुई है, अर्थात ईश्वर में। यह तभी संभव है जब सभी सिद्धांतों का जीवन में अनुसरण किया जाए।

जगद्गुरु श्री रामभद्राचार्य, दुनिया जिन्हें नेत्रहीन कहती है।

पिंकी कुंडू

सच यह है कि उन्होंने वह देखा है, जो आँखों वाले भी नहीं देख पाए। आज वे 75 वर्ष के हैं।

जन्म से दृष्टिहीन पर ज्ञान की वह ज्योति, जो उनके भीतर जलती है, उसके सामने सूरज भी संकोच कर जाए। उनका नाम है — जगद्गुरु श्री रामभद्राचार्य।

बचपन से ही उनका जीवन किसी चमत्कार से कम नहीं रहा स्कूल की हर कक्षा में — 99 प्रतिशत से कम अंक कभी नहीं। जिसे लोग 'अंधा' कहते रहे, वह शास्त्रों के अंधकार को प्रकाश में बदलता चला गया।

230 से अधिक पुस्तकें संस्कृत, वेद, रामायण, दर्शन, व्याकरण — ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ उनका हस्ताक्षर न हो।

कई विश्वविद्यालयों ने उन्हें महामहोपाध्याय और जगद्गुरु की उपाधि दी। लेकिन इतिहास उन्हें सबसे अधिक याद रखेगा श्री राम जन्मभूमि मामले के लिए।

जब एक संत अदालत में खड़ा हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट। तीन सौ वकीलों से भरी अदालत। तर्क, शोर, राजनीति और अविश्वास से भरा वातावरण।

और बीच में खड़े — एक नेत्रविहीन संत।

उनसे पूछा गया — "क्या रामचरितमानस में राम जन्मभूमि का कोई उल्लेख है?" उन्होंने बिना रुके, बिना झिझके तुलसीदास की चौपाई सुना दी।

फिर अगला वार हुआ — "वेदों में क्या प्रमाण है कि श्रीराम का जन्म यहीं हुआ?"

इस बार उत्तर और भी गहरा था।

उन्होंने कहा — "अथर्ववेद, दशम कांड, इकतीसवें मंत्र में इसका स्पष्ट उल्लेख है।"

अदालत सन्न रह गई। और तभी न्यायाधीशों की पीठ से — जिसमें एक मुस्लिम न्यायाधीश भी थे — वह ऐतिहासिक वाक्य निकला: "सर, आप एक दिव्य आत्मा हैं।"

441 साक्ष्य। उनमें से 437 को न्यायालय ने स्वीकार किया।

सोचिए — जिसे दुनिया 'अंधा' कहती है,

वह भारत के सबसे विवादित इतिहास को प्रमाणों से देख रहा था।

जब राजनीति भी मौन हो गई जब एक राजनीतिक हलफनामे में कहा गया कि "राम का जन्म नहीं हुआ," तो यह संत मौन नहीं रहा। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री को पत्र लिखा — और केवल एक पंक्ति ने सबको निरुत्तर कर दिया:

"आपके गुरु ग्रंथ साहिब में राम नाम का उल्लेख 5600 बार है।" यह तर्क नहीं था।

यह सांस्कृतिक स्मृति थी।

क्या वे सच में अंधे हैं? एक बार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे कहा — "मैं आपके इलाज और दर्शन की व्यवस्था कर सकती हूँ।"

संत मुस्कुराए और बोले — "मैं दुनिया नहीं देखना चाहता।" बाद में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा — "मैं अंधा नहीं हूँ। मैंने कभी अंधे होने की रियायत नहीं ली। मैं भगवान श्री राम को बहुत पास से देखता हूँ।" और उस क्षण समझ में आता है — आँखों से देखना और दर्शन करना दो अलग बातें हैं।

सनातन की जीवित मशाल ऐसे संत ग्रंथों में नहीं, समय में जन्म लेते हैं। वे इसलिए नहीं होते कि चमत्कार दिखाएँ,

बल्कि इसलिए होते हैं कि सभ्यता को आईना दिखा सकें। अगर आज सनातन संस्कृति खड़ी है, तो उसके पीछे ऐसे ही मौन तपस्वियों की तपस्या है।

ृरउन्हें नेत्रहीन कहना शायद हमारी सबसे बड़ी दृष्टिहीनता है।

प्रतिशोध और पुनर्जन्म: देवी वेदवती से सीता बनने की गाथा

पिंकी कुंडू

अयोध्या के राजभवन में शांति छाई हुई थी। प्रभु श्रीराम सिंहासन पर विराजमान थे और उनके समक्ष बैठे थे महान ऋषि अगस्त्य। श्रीराम ने जिज्ञासावश पूछा, ₹हे मुनिवर! रावण का वध मेरे हाथों हुआ, पर क्या इसके पीछे कोई पूर्वलिखित विधान था?₹

ऋषि अगस्त्य मुस्कुराए और बोले, ₹राघवेन्द्र! रावण का विनाश तो बहुत पहले एक तपस्विनी के शाप से निश्चित हो चुका था। सुनो, वह कथा₹

1. हिमालय की वो दिव्य तपस्विनी बात उस समय की है जब रावण अपने शक्ति के मद में तीनों लोकों को कुचल रहा था। अपनी दिग्विजय यात्रा के दौरान वह हिमालय के घने वनों में पहुँचा। वहाँ उसने एक दृश्य देखा जिसने उसके कदमों को रोक दिया। एक अत्यंत रूपवती कन्या, जिसका मुख मंडल सूर्य के समान तेजस्वी था, घोर तपस्या में लीन थी। वह जटा धारण किए हुए थी और मृगचर्म पहने थी, फिर भी उसकी सुंदरता स्वर्ग की अप्सराओं को भी लज्जित कर रही थी। कामवासना से अंधा होकर रावण उसके समीप गया और पूछा, ₹हे सुंदरी! तुम कौन हो और इस बीहड़ वन में यह कठिन तप क्यों कर रही हो?₹

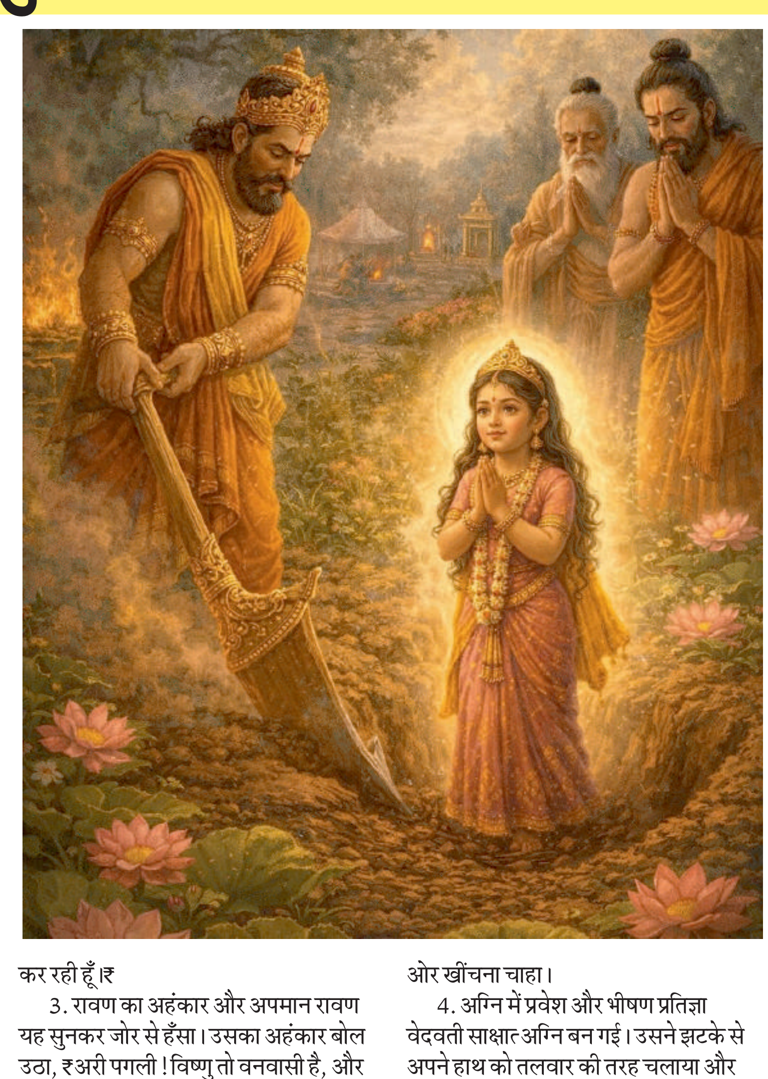

2. वेदवती का संकल्प उस तेजस्वी कन्या ने नेत्र खोले और शांत भाव से अपना परिचय दिया: ₹राजन! मेरे पिता देवगुरु बृहस्पति के पुत्र 'कुशध्वज' थे। मैं उन्हीं की पुत्री हूँ और मेरा नाम 'वेदवती' है। मेरे पिता का यह दृढ़ संकल्प था कि वे मेरा विवाह केवल और केवल त्रिभुवन स्वामी भगवान विष्णु से ही करेंगे। किसी अन्य देवता या दानव को वे मुझे नहीं सौंपना चाहते थे।₹ वेदवती का कंठ भर आया, ₹परंतु, दैत्यराज शंभू को यह सहन नहीं हुआ। उसने छल से, निद्रावस्था में मेरे पिता की हत्या कर दी। मेरी माता यह वियोग सहन न कर सकीं और पिता की चिता में सती हो गईं। अब मैं अनाथ हूँ, किंतु मेरा संकल्प अटल है। मैं अपने पिता की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान नारायण को पति रूप में पाने हेतु यह घोर तप कर रही हूँ।₹

3. रावण का अहंकार और अपमान रावण यह सुनकर जोर से हँसा। उसका अहंकार बोल उठा, ₹अरी पगली! विष्णु तो वनवासी है, और मैं? मैं लंकापति दशग्रीव हूँ! तीनों लोक मुझसे थर-थर कांपते हैं। उस विष्णु को छोड़ और मेरी पटरानी बन जा। सुख भोग।₹ वेदवती ने घृणा से उत्तर दिया, ₹पापी! त्रिभुवन पति नारायण के अतिरिक्त मेरा मन किसी और के लिए नहीं है। अपनी जुबान बंद रख।₹ तिरस्कार सुनकर रावण का पौरुष आहत हो गया। क्रोध और काम के वेग में उसने वेदवती के केश (बाल) पकड़ लिए और उसे अपनी ओर खींचना चाहा।

4. अग्नि में प्रवेश और भीषण प्रतिज्ञा वेदवती साक्षात अग्नि बन गई। उसने झटके से अपने हाथ को तलवार की तरह चलाया और अपने ही केश काट दिए, जिन्हें रावण ने स्पर्श किया था। उसकी आँखों से ज्वाला फूट पड़ी। उसने गरज कर कहा: ₹दुष्ट! तूने मेरे पवित्र शरीर को स्पर्श कर अपवित्र कर दिया है। अब मैं इस देह को नहीं रखूँगी। पर सुन ले, मैं तेरे विनाश के लिए पुनः जन्म लूँगी। जिस नारी शक्ति का तूने अपमान किया है, वही नारी तेरी मृत्यु का कारण बनेगी!₹ इतना कहकर वेदवती ने योगबल से अग्नि प्रकट की और रावण के देखते - देखते स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया। रावण हतप्रभ खड़ा रह गया।

5. कमल, समुद्र और मिथिला (पुनर्जन्म की यात्रा) ऋषि अगस्त्य कथा को आगे बढ़ाते हुए बोले — ₹हे राम! वह वेदवती अपने वचन की पक्की थी।₹ अगले जन्म में वह एक सुंदर कमल के फूल से प्रकट हुई। रावण उस सुंदर शिशु को देखकर मोहित हो गया और उसे अपने साथ लंका ले गया। जब उसने अपने मंत्रियों को वह कन्या दिखाई, तो एक ज्ञानी मंत्री ने गणना करके कहा, ₹महाराज! अनर्थ हो गया। यह कन्या साक्षात मृत्यु है। यदि यह लंका में रही, तो राक्षस कुल का नाश निश्चित है।₹ मृत्यु के भय से रावण ने उस नवजात कन्या को एक मंजूषा (बक्से) में बंद करके समुद्र में फेंकवा दिया। लहरों ने उसे बहाते-बहाते भारतवर्ष के तट पर ला दिया। वहाँ से वह भूदेवी की गोद में समा गई और भूमि के भीतर सुरक्षित होकर मिथिला पहुँच गई।

6. सीता का प्राकट्य समय का चक्र घूमा। मिथिला में अकाल पड़ा था। राजा जनक यज्ञ के लिए भूमि जोत रहे थे। तभी उनके हल का नुकीला भाग (जिसे 'सीत' कहते हैं) उस मंजूषा से टकराया। राजा जनक ने उसे खोला, तो उसमें वही वेदवती, एक दिव्य कन्या के रूप में मुस्कुरा रही थी। हल की रेखा (सीता) से प्राप्त होने के कारण उनका नाम 'सीता' पड़ा। ऋषि अगस्त्य ने हाथ जोड़कर श्रीराम से कहा: ₹हे महाबाहु! मिथिला नरेश की पुत्री जानकी ही वह वेदवती हैं। पूर्व जन्म में सतयुग में उन्होंने रावण के वध की प्रतिज्ञा की थी, और त्रेतायुग में आपके साथ मिलकर उस प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। आप ही सनातन विष्णु हैं और सीता ही वह लक्ष्मी स्वरूपा वेदवती हैं।₹ यह सुनकर श्रीराम गंभीर हो गए और उन्होंने अपनी शक्ति, अपनी सीता के त्याग को मन ही मन प्रणाम किया।

शिक्षा: नारी का अपमान ही रावण जैसे महाशक्तिशाली के विनाश का बीज बना। जहाँ नारी का सम्मान नहीं, वहाँ विनाश निश्चित है।

माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव को अर्घ्य कैसे दें? जानें नियम

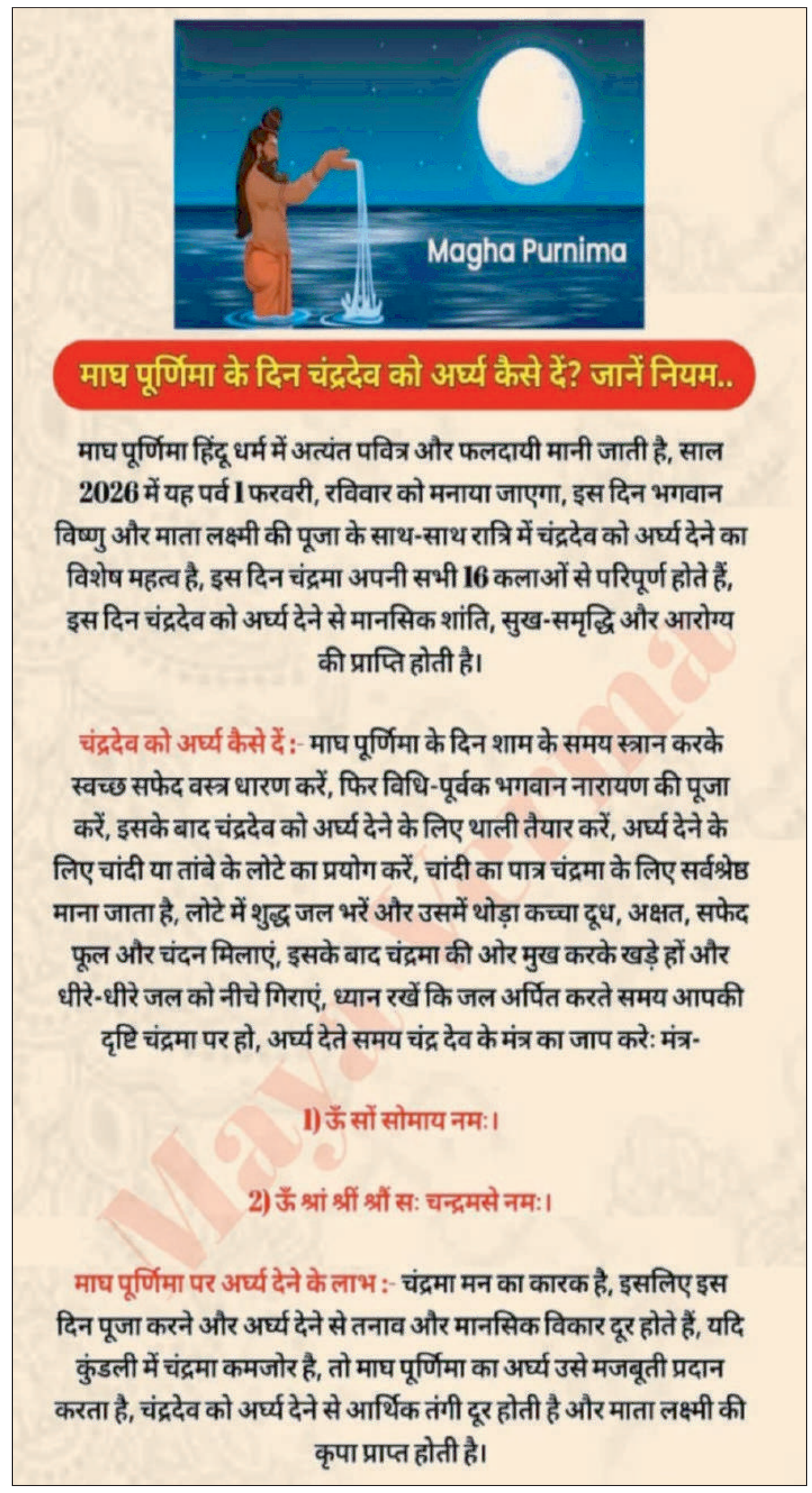

पिंकी कुंडू

माघ पूर्णिमा हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और फलदायी मानी जाती है, साल 2026 में यह पर्व 1 फरवरी, रविवार को मनाया जाएगा, इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के साथ-साथ रात्रि में चंद्रदेव को अर्घ्य देने का विशेष महत्व है, इस दिन चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं, इस दिन चंद्रदेव को अर्घ्य देने से मानसिक शांति, सुख-समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है।

चंद्रदेव को अर्घ्य कैसे दें:- माघ पूर्णिमा के दिन शाम के समय स्नान करके स्वच्छ सफेद वस्त्र धारण करें, फिर विधि-पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करें, इसके बाद चंद्रदेव को अर्घ्य देने के लिए थाली तैयार करें, अर्घ्य देने के लिए चांदी या तांबे के लोटे का प्रयोग करें, चांदी का पात्र चंद्रमा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, लोटे में शुद्ध जल भरें और उसमें थोड़ा कच्चा दूध, अक्षत, सफेद फूल और चंदन मिलाएं, इसके बाद चंद्रमा की ओर मुख करके खड़े हों और धीरे-धीरे जल को नीचे गिराएं, ध्यान रखें कि जल अर्पित करते समय आपकी दृष्टि चंद्रमा पर हो, अर्घ्य देते समय चंद्र देव के मंत्र का जाप करे: मंत्र-

1) ॐ सों सोमाय नमः ।

2) ॐ श्रां श्रीं श्रौं सः चन्द्रमसे नमः।

माघ पूर्णिमा पर अर्घ्य देने के लाभ: चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए इस दिन पूजा करने और अर्घ्य देने से तनाव और मानसिक विकार दूर होते हैं, यदि कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, तो माघ पूर्णिमा का अर्घ्य उसे मजबूती प्रदान करता है, चंद्रदेव को अर्घ्य देने से आर्थिक तंगी दूर होती है और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है।

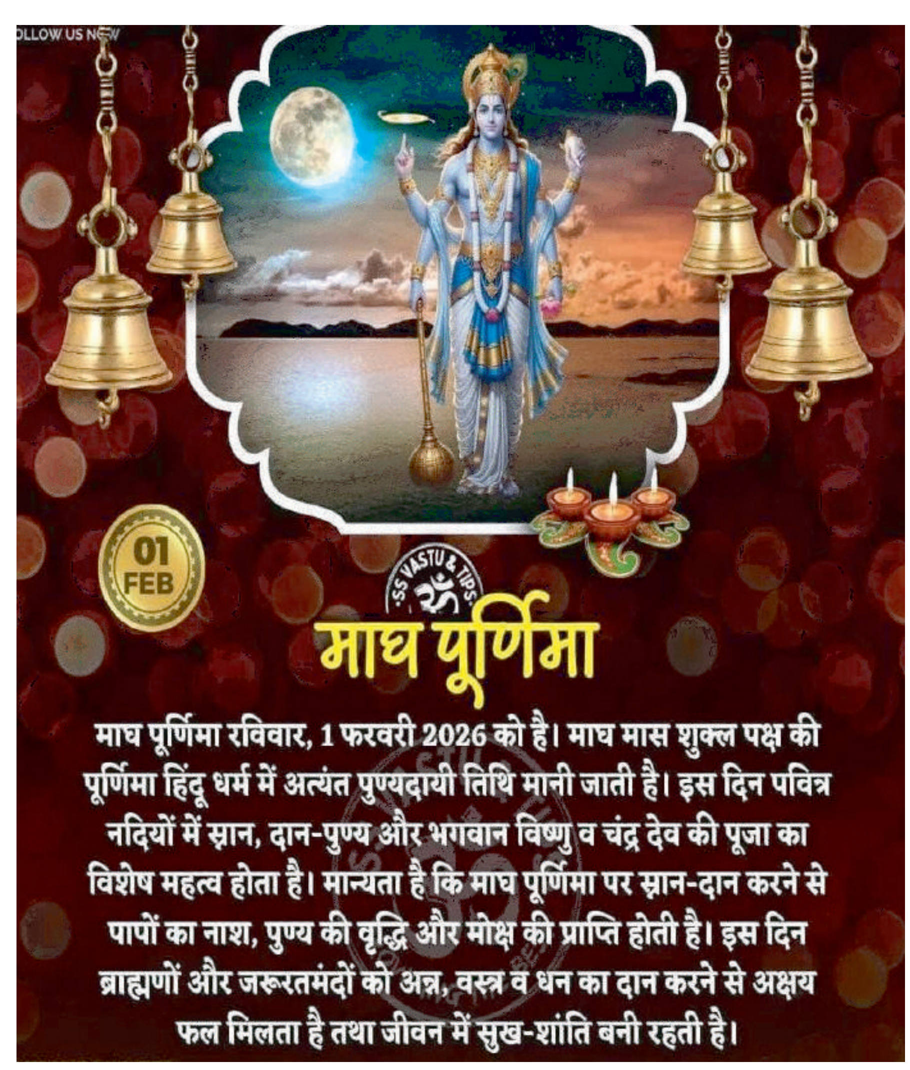

कृषि मंत्री राणा ने किया बागवानी अनुसंधान केंद्र रईया का दौरा

बागवानी विशेषज्ञों को क्षेत्र की मांग के अनुसार नई सब्जियों और फलों की किस्म तैयार करने के दिए निर्देश

परिवहन विशेष न्यूज

बागवानी से किसानों की आय कई गुना बढ़ेगी : बोले कृषि मंत्री

झज्जर, 31 जनवरी। प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के अंतर्गत रईया स्थित बागवानी अनुसंधान केंद्र का दौरा किया और किसानों के कल्याण के लिए केंद्र में चल रही गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति निरंतर किसानों की आय बढ़ाने की रही है। पूर्व कृषि मंत्री औम प्रकाश धनखड़ ने मोदी की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए इस क्षेत्र को बागवानी केंद्र रईया और मुनीमपुर में बीज एवं फूल उत्कृष्टता केंद्र खोलकर क्षेत्र के किसानों को बड़ी सौगात दी थी। पीढी दर पीढी जोत घटती जा रही है , ऐसे में परंपरागत खेती की बजाय किसानों को बागवानी की खेती कर अपनी आय बढ़ानी होगी। ये केंद्र किसानों के लिए बड़े लाभकारी सिद्ध होंगे।

डॉ. धर्मपाल चौधरी, निदेशक अनुसंधान ने विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. सुरेश कुमार मल्होत्रा के नेतृत्व में केंद्र में किए जा रहे अनुसंधान कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र में जीरा, अजवायन, सौंफ जैसी बीज मसाला फसलें और अंजीर, कमलम जैसे नए फलों और मसालों की खेती शुरू की गई है, जो इस क्षेत्र के लिए नई हैं। कृषि मंत्री ने भिवानी का उदाहरण देते कहा कि इस क्षेत्र में खजूर की खेती शुरू की जाए, जिससे किसानों को लाभ हो सके।

रईया केंद्र में पहुंचने पर ग्राम पंचायत ने सरपंच की अगुवाई में कृषि मंत्री का पगड़ी बांधकर स्वागत किया। डॉ. सत्यपाल यादव, प्रभारी बागवानी अनुसंधान केंद्र रईया ने मंत्री का स्वागत किया और आश्वासन दिया कि यह केंद्र किसानों के लिए वरदान साबित होगा और भविष्य में किसानों को सभी पौध सामग्री प्रदान करेगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। कृषि मंत्री ने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी और जल्द समाधान का आश्वासन दिया। इस अवसर पर संदीप हसनपुर, विनोद बाढसा सहित गणमान्य लोग और जागरूक किसान मौजूद रहे।

पीएम किसान योजना सहित सभी कृषि योजनाओं का लाभ फार्मर आईडी से ही मिलेगा : डीसी

डिजिटल एग्री स्टैक फार्मर आईडी अभियान में तेजी लाने के निर्देश

परिवहन विशेष न्यूज

झज्जर, 31 जनवरी। उपायुक्त स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने डिजिटल एग्री स्टैक फार्मर आईडी अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों एवं फील्ड में कार्यरत टीमों को कार्य में और अधिक तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए हैं।

डीसी ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा डिजिटल एग्री स्टैक फार्मर आईडी अभियान को मिशन मोड में संचालित किया जा रहा है तथा सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस महत्वपूर्ण कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और निर्धारित समय-सीमा के भीतर शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करना अनिवार्य है।

उपायुक्त ने कहा कि प्रत्येक किसान की फार्मर आईडी बनना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भविष्य में पीएम किसान सम्मान निधि योजना सहित किसानों को मिलने वाली सभी कृषि संबंधी सरकारी योजनाओं, अनुदान, सब्सिडी एवं सेवाओं का लाभ इसी आईडी के माध्यम से दिया जाएगा। फार्मर आईडी के अभाव में किसान विभिन्न योजनाओं के लाभ से वंचित रह सकते हैं, इसलिए अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र किसान छूटने न पाए।

डीसी पाटिल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांव-गांव जाकर विशेष कैंपों का आयोजन कर किसानों को फार्मर आईडी के महत्व के बारे में जागरूक किया जाए तथा मौके पर ही आईडी जनरेट की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि तकनीकी या दस्तावेज संबंधी समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए, ताकि अभियान की गति प्रभावित न हो।

उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि फील्ड स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए और प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत की जाए, ताकि लक्ष्य की समयबद्ध पूर्ति सुनिश्चित हो सके।

शहर और बाजारों को जाम फ्री बनाने के लिए अतिक्रमण हटाना जरूरी: एसडीएम

प्रशासन ने रेलवे रोड को कराया अतिक्रमण मुक्त , दुकानदारों से सहयोग का आह्वान

अतिक्रमण करने वालों के 42 हजार रुपए के और नो पार्किंग में खड़े 50 वाहनों के किए चालान

जाम फ्री होने से वायु प्रदूषण कम होगा और आवागमन सुगम होगा : बोले एसडीएम

परिवहन विशेष न्यूज

बहादुरगढ़, 31 जनवरी। शहर और बाजारों को जाम फ्री रखने के लिए अतिक्रमण हटाना जरूरी है। इसमें सभी दुकानदार सहयोगी बनें। मार्केट जाम फ्री रहेगी तो ग्राहक भी सुगमता से खरीदारी करेंगे। इसमें राहगीरों के साथ साथ दुकानदारों का भी फायदा है। शहर के लोगों की शिकायतों का संज्ञान लेते एसडीएम के आदेश पर शनिवार को नगर परिषद और ट्रैफिक पुलिस ने रेलवे रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया और नो पार्किंग एरिया में खड़े वाहनों के चालान किए।

एसडीएम अभिनव सिवाच ने मौके का जायजा लेते हुए बताया कि अतिक्रमणकारियों के 42 हजार रुपए के चालान किए गए है और नो पार्किंग में खड़े 50 वाहनों के भी चालान किए। नियमों की अनदेखी करने पर कई वाहनों को इंपाउंड भी किया गया। रेलवे रोड से लेकर विश्वकर्मा धर्मशाला तक प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी रही।।

अतिक्रमण हटाओ अभियान उपरांत रेलवे रोड खुला खुला नजर आया। लोगों को जाम से राहत मिली और शहर के नागरिकों और राहगीरों ने प्रशासन की कार्रवाई की खुलकर प्रशंसा की।

राहगीरों ने कहा कि रेलवे रोड पर दुकानों के बाहर काफी दूर तक सामान रख दिया जाता है। इसके अलावा रेहड़ी-पटरी और बेतरतीब ढंग से की गई पार्किंग से हालात और बिगड़ जाते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि यहां आए दिन जाम लगता है और आमजन को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। इन्हीं शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम अभिनव सिवाच ने खुद मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया।

इस दौरान ढाई हजार रुपये से लेकर दस हजार रुपये तक के चालान किए गए।

एसडीएम अभिनव सिवाच ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि रेलवे रोड लगभग 60 फुट चौड़ा मार्ग है, राहगीरों के लिए 60 फुट चौड़ा रोड रहना चाहिए। इस पर अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह महत्वपूर्ण मार्ग है जो शहर को रेलवे स्टेशन से जोड़ता है।

उन्होंने दुकानदारों से अतिक्रमण ना करने और नागरिकों से अवैध पार्किंग ना करने का आह्वान किया। प्रशासन का सहयोग करें। एसडीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि यह अभियान यहीं नहीं रुकेगा, जनहित में आगे भी शहर में लगातार इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी और जल्द ही अन्य सड़कों से भी अतिक्रमण हटाया जाएगा। बाजारों में अतिक्रमण को निरंतर प्रशासन के पास शिकायत आ रही हैं। अपने शहर और बाजारों को जाम फ्री रखने में सहयोगी बनें। इससे वायु प्रदूषण भी कम होगा। लोगों को आवागमन में सहूलियत होगी।

एसएचओ ट्रैफिक सतीश कुमार, सिटी थाना से एसआई धर्मेंद्र सहित नगर परिषद के अधिकारियों ने संयुक्त कार्रवाई की ।

राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी 6 से 8 फरवरी तक कुरुक्षेत्र में

झज्जर के पशुपालकों के लिए बसों की विशेष व्यवस्था

झज्जर, 31 जनवरी। कुरुक्षेत्र स्थित कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड मेला ग्राउंड में दिनांक 06 फरवरी से 08 फरवरी, 2026 तक तीन दिवसीय 41वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। इस राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में प्रदेश भर से लगभग 1500 उन्नत नस्ल के पशु विभिन्न श्रेणियों में भाग लेंगे। प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य उत्तम नस्ल के पशुओं का प्रदर्शन कर नस्ल सुधार के लिए पशुपालकों को प्रेरित करना तथा दूध उत्पादन में वृद्धि कर किसानों की आय बढ़ाना है।

यह जानकारी पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग के उपनिदेशक डॉ. मनीष डबास ने दी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में विभाग के सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ताकि वे अपने-अपने क्षेत्रों में पशुपालकों से संपर्क कर आयोजन की तैयारियों में सक्रिय रूप से जुट सकें। उन्होंने पशुपालकों से आग्रह किया कि वे अपने उत्तम नस्ल के पशुओं का विवरण संबंधित पशु चिकित्सक को समय रहते उपलब्ध कराएं तथा पशु प्रवेश याचिका पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

डॉ. मनीष डबास ने बताया कि प्रदर्शनी में मुर्राह भैंस, देशी नस्ल की गायें जैसे हरियाणा, साहीवाल, गिर, थारपारकर, राठी व बेलाही, क्रॉस ब्रीड गाय, घोड़े व गधे, ऊंट, भेड़ (नाली नस्ल, हिसार डेल नस्ल), बकरी एवं गौशाला पशु भाग लेंगे। प्रदर्शनी के दौरान चयनित सर्वश्रेष्ठ पशुओं को नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि पशु मालिकों को प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए अपने साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, कैंसिल चैक तथा परिवार पहचान पत्र (पीपीपी आईडी) अनिवार्य रूप से लाने होंगे।

उपनिदेशक ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि पशुपालन विभाग झज्जर द्वारा जिला के पशुपालकों को प्रदर्शनी स्थल तक ले जाने एवं वापस लाने के लिए प्रतिदिन 10 बसों की विशेष व्यवस्था की गई है। उन्होंने जिला के सभी पशुपालकों से इस राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया।

साउथ दिल्ली पत्रकार संघ के रजिस्टर्ड होने पर पत्रकारों का मुंह मीठा कराकर कई अहम विषयों पर हुई चर्चा

स्वतंत्र सिंह भुल्लर नई दिल्ली

नई दिल्ली ।साउथ दिल्ली पत्रकार संघ की पांचवीं बैठक विश्वकर्मा कॉलोनी में हर्षोल्लास के माहौल में सम्पन्न हुआ ।जिसमें भारी संख्या में पहुंच कर पत्रकार बंधुओं ने अपनी एकता का परिचय दिया ।आपको बता दे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट साउथ दिल्ली पत्रकार संघ को मिल गया है। उसकी भी खुशी थी और इस खुशी के अवसर पर लड्डू खिलाकर सभी पत्रकारों को बधाई दी गई।

रजिस्ट्रेशन के बाद यह पहली बैठक थी जिसमें भारी संख्या में पत्रकार बंधु मौजूद रहे। अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षा में बैठक की शुरुवात की गई ।बैठक में सभी साथियों ने अपने अपने विचार रखे, साथ ही उनके विचारों पर चर्चाएं भी हुई, और अब संगठन को और मजबूत करने के साथ साथ साउथ दिल्ली के सभी पत्रकार साथी जो अभी ग्रुप से नहीं जुड़े है उनको जोड़ने का भी प्रयास किया जाएगा। संगठन सभी के लिए है सभी के साथ है इसलिए जो भी साथी पत्रकार साउथ दिल्ली पत्रकार संगठन के ग्रुप से जुड़ना चाहता है वह संगठन के साथियों से मिल सकता है और अपने डॉक्यूमेंट जमा कर के संगठन का सदस्य बन सकता है ।दरवाजा सभी के लिए खुला हुआ है और संगठन चाहता है कि दक्षिणी दिल्ली का हर पत्रकार इस संगठन से जुड़े। जिससे संगठन की अहमियत बढ़ेगी ओर पत्रकार का मान सम्मान भी मजबूती के साथ दक्षिणी दिल्ली में बरकरार रहेगा। साथ ही सालाना मेंबरशिप शुल्क पर भी विचार विमर्श किया गया ओर पत्रकार साथियो की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर भी चर्चा की गई।

आज की बैठक सार्थक रही ओर सभी के विचार विमर्श के बाद अध्यक्ष जी ने ग्रुप में चल रही खबरों के साथ उन पर भी प्रकाश डाला ओर सभी के सम्मुख कहा कि जो संगठन की कार्यकारणी 19 अगस्त को चुनी गई थी वहीं रखेगी उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा हा यह जरूर है कि जो संगठन की 3 बैठकों में नहीं आता ओर वह कार्यकारणी का सदस्य है फिर उसपर संगठन विचार विमर्श के बाद करवाई कर सकता है ।एक सुझाव यह भी रखा गया कि कार्यकारणी में जो सदस्य समय नहीं दे पा रहे है या बैठकों में नहीं आ पा रहे है और संगठन को सूचित कर के अपना पद छोड़ सकता है और वह सिर्फ सदस्य बन के जुड़ा रहे जिससे उसका पद किसी ओर जिम्मेदार साथी को संगठन में दिया जा सके।

कई मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ ओर चर्चाओं के साथ ही दिल की बात भी निकलती है जो संगठन को मजबूती की ओर अग्रसर भी करती है। आइए ओर साउथ दिल्ली पत्रकार संगठन को दक्षिणी दिल्ली के साथ ही साथ दिल्ली का सबसे मजबूत संगठन बनाने में अपनी अपनी भागेदारी को निभाए।

सांबा ड्रोन अलर्ट: पाकिस्तान के संदिग्ध यूएवी घुसपैठ से सीमा पर बढ़ी चौकसी

संगिनी घोष,

जम्मू-कश्मीर के सांबा सेक्टर में गुरुवार को पाकिस्तान की ओर से एक संदिग्ध मानव रहित ड्रोन (यूएवी) के भारतीय हवाई क्षेत्र में कुछ देर के लिए प्रवेश करने की सूचना मिली, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। यह घटना भले ही थोड़े समय की रही, लेकिन इसने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर लगातार सतर्कता की जरूरत को फिर से उजागर किया है।

सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, ड्रोन को रडार निगरानी प्रणाली के जरिए पकड़ा गया, जिसके तुरंत बाद जवानों को अलर्ट किया गया। संभावित खतरे को देखते हुए आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान भी शुरू किया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ड्रोन के जरिए कोई संदिग्ध सामग्री या तस्करी का प्रयास न हुआ हो।

सीमा फोकसः त्वरित ट्रैकिंग और जमीनी जांच

अधिकारियों ने बताया कि ड्रोन की गतिविधि को कुछ समय तक ट्रैक किया गया, लेकिन बाद में वह रडार की सीमा से बाहर चला गया। इसके तुरंत बाद संवेदनशील क्षेत्रों में जमीनी टीमें भेजी गईं, जो इस तरह की हवाई घुसपैठ को लेकर सुरक्षा बलों की गंभीरता को दर्शाता है।

सीमावर्ती जिलों में ड्रोन से जुड़ी घटनाएं लगातार चिंता का विषय बनती जा रही हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल अवैध गतिविधियों के लिए बढ़ रहा है।

सांबा सेक्टर क्यों है संवेदनशील?

सांबा क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय सीमा के बेहद करीब स्थित है और पिछले कुछ वर्षों में यहां निगरानी और चौकसी बढ़ाई गई है। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं क्योंकि ड्रोन का उपयोग पहले भी हथियार, नशीले पदार्थ या संचार उपकरण सीमा पार पहुंचाने के मामलों में किया जा चुका है।

मुख्यबिंदु

घटना स्थलः सांबा सेक्टर, जम्मू-कश्मीर

संदिग्ध स्रोतः पाकिस्तान की ओर से ड्रोन आने की आशंका

कार्रवाईः रडार ट्रैकिंग के बाद जवानों की तैनाती

सुरक्षा कदमः आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान

चिंताः निगरानी या सीमा पार तस्करी की संभावना

स्थितिः जांच जारी, सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर

राष्ट्रीय सुरक्षा असर और आगे की राह

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं यह दिखाती हैं कि सीमा पर खतरे अब तकनीक के साथ नए रूप ले रहे हैं। जहां पारंपरिक घुसपैठ चिंता का विषय है, वहीं ड्रोन के बढ़ते इस्तेमाल ने सुरक्षा एजेंसियों के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है।

फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है और तलाशी अभियान पूरा होने के बाद स्थिति और स्पष्ट होने की उम्मीद है।

डिजिटल मेटा डिस्क्रिप्शन (SEO):

जम्मू-कश्मीर के सांबा सेक्टर में संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन के भारतीय सीमा में प्रवेश से सुरक्षा बलों ने रडार ट्रैकिंग और तलाशी अभियान चलाया। घटना ने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सतर्कता को फिर से रेखांकित किया है।

विराट व ऐतिहासिक देवघर पुस्तक मेला में आयोजित "वंदे -मातरम" कार्यक्रम ने दर्शको का मन मोहा

परिवहन विशेष न्यूज

देवघर । स्थानीय बीएड कॉलेज प्रान्गण में ज्ञान का महाकुंभ, महाविद्या द्वारा आयोजित 23वाँ विराट पुस्तक मेला में भव्य ‟वंदें-मातरम” कार्यक्रम ने पूरे माहौल को देश भक्ति, उत्साह और जोश से भर दिया। वंदे मातरम के 150 वी वर्षगाठ को समर्पित वंदे भारत के इस वंदे मातरम के ऐतिहासिक कार्यक्रम के उम्दा प्रदर्शन ने लोगो को संस्कृति, देश भक्ति, जोश और उत्साह से भर दिया। इस कार्यक्रम की अद्भुत, शानदार रोचक प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया। मंचासीन कलाकारों ने अपने अदम्य कौशल से देश की सांस्कृतिक एकता, संस्कृति, परंपरा, कला और गौरव का प्रभावशाली ढंग से अद्भुत प्रदर्शन व झलक प्रस्तुत किया ।इस अविस्मरणीय अदभूत, शानदार, भव्य व रोचक आयोजन पर राष्ट्र जागृति मंच के जिला अध्यक्ष श्री प्रभाष गुप्ता ने आयोजक के तमाम सदस्यों एवं कलाकारों के प्रति आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद व्यक्त किया है।

डिप्टी मेयर मुकेश सारस्वत का किया सम्मान

परिवहन विशेषन्यूज

मथुरा जनपद के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनमें से यूजीसी कानून पर किसी ने अपना पक्ष न रखने से सामान्य वर्ग में ऐसे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ रोष व्याप्त होने के बाद सामान्य वर्गों के द्वारा आये दिन यूजीसी के खिलाफ जगह जगह बेठके आयोजित हो रही हैं । सामान्य वर्गों से जनपद मथुरा के प्रतिनिधियों के साथ सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ विरोध किया जा रहा है । इसके बावजूद सामान्य वर्ग से आने वाले मथुरा नगर निगम के उपसभापति (डिप्टी मेयर) मुकेश सारस्वत उर्फ मुकेश प्रधान के द्वारा सत्ता पक्ष के होने के बाद भी उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर यूजीसी कानून से सामान्य वर्ग से आने वाले छात्रों को होने वाली में समस्या से अवगत कराते हुए पुण्य विचार करने के लिए अनुरोध किया है इससे ब्राह्मण समाज में मुकेश सारस्वत के प्रति समाज में विश्वसनीयता बड़ी है इसके लिए सामाजिक कार्यकर्ता विनोद दीक्षित ने दुपट्टा पहनकर समाज की तरफ से मुकेश सारस्वत को दुपट्टा पहनकर सम्मानित किया गया । अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम ने मुकेश सारस्वत को अपना आर्शीवाद देते हुए कहा समाज इन से प्ररेणा लेनी चाहिए । डॉ मनोज मोहन शास्त्री शास्त्री ने मुकेश सारस्वत को अपना आशीर्वाद देते हुए का अगर आप समाज से रहते हुए समाज के लिए काम करेंगे तो निश्चित तौर पर राजनीति में सफल रहेंगे समाज जो चाहता है उसके अनुरूपी आपको काम करना चाहिए आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता ।

बांग्लादेश के हालात को देखते हुए भारत में सिर्फ़ स्वर्ण एकता नहीं बल्कि हिन्दू एकता जरूरी

परिवहन विशेष न्यूज

बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के द्वारा हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, तब भारत में सिर्फ़ स्वर्ण एकता की नहीं बल्कि सभी हिंदुओं में एकता होना बहुत जरूरी है।

उत्तरप्रदेश। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करतें हुए लोगों ने मोदी सरकार से अपील की कि मोदी सरकार इस चिंताजनक मुद्दे को बांग्लादेश सरकार के सामने राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर बार-बार उठाऐ और 12 फरवरी को बंगलादेश में चुनाव होने तक लगातार नजर बनाए रहे। हालिया घटनाओं में हिन्दू अल्पसंख्यकों के घरों, संपत्तियों, पूजा स्थलों और निर्दोष पुजारियों पर हमले हुए हैं।

उन्होंने सभी से देशहित में, हिन्दू एकता की अपील करते हुए कहा कि बांग्लादेश के हालात को देखते हुए भारत में सिर्फ़ स्वर्ण एकता नहीं बल्कि हिन्दू एकता बहुत जरूरी हैं। हिन्दुओं की सभी जातियों में एकता होना बेह्द आवश्यक है। एससी, एसटी और ओबीसी के सामने ब्राह्मण, वैश्य, राजपूत, कायस्थ वर्ग को खड़ा नहीं किया जा सकता। वैसे भी आरक्षित वर्ग में ओबीसी को शामिल करने के बाद समाज में सामान्य वर्ग का प्रतिशत लगभग सिर्फ़ 15 % ही रह जाता है।

ऐसे में कोई यह कल्पना नहीं कर सकता है कि बंगलादेश में अल्पसंख्यक हिन्दुओं और उनके सैकड़ों मंदिरों व बच्चें महिलाओं पर हमले हो, निर्दोष एवं शांतिप्रिय पुजारियों को मंदिर के अंदर जिन्दा जलाया जाएं। वैसे भी जब पड़ोसी राज्य बंगाल में कट्टरपंथियों के द्वारा हिंदुओं को प्रताड़ित कर पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा हो तब हिन्दुओं में सिर्फ़ स्वर्ण एकता की नहीं बल्कि सभी हिंदुओं में एकता होना जरूरी है। बिरोध कीजिए लेक़नि आज़ मोदी योगी के बिरोध में यह भी मत भूलना कि पहलगांम में पाकिस्तान के आतंकियों ने कोई जाति नहीं पूछी थी सिर्फ़ हिन्दू देखकर उनकी महिलाओं और बच्चों के सामने ही सीधे मांथे में गोली मारी थी।

उन्होंने आगे कहा कि हिंदू चाहे सामान्य वर्ग का हो या फिर एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का सभी में एकता होना जरूरी है। किसी को भी ऐसा काम कभी भी नहीं करना चाहिए जिससे ग़रीब, असहाय और कमजोरों को पीड़ा हो। जातिबाद से

हिंदुओं में भेदभाव बढ़ाता है। आरक्षित वर्ग के लोगों को भी अब अपने मन से इस भावना को निकाल देना चाहिए कि सामान्य वर्ग के द्वारा किसी प्रकार का अपमान पूर्ण व्यवहार किया जाएगा। जहां तक सामान्य वर्ग का सवाल है तो पुराने कहानी किस्सों को आधार बनाकर मौजूदा समय में अपराधी नहीं माना जा सकता।

मोदी सरकार द्वारा अपने राजनयिकों के सभी परिवारों को बांग्लादेश से वापस बुलाने के फैसले से ढाका में मची हलचल मच

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अपने राजनयिकों के सभी परिवारों को बांग्लादेश से वापस बुलाने के फैसले पर ढाका में हलचल मच गई है। भारत ने आगामी चुनावों और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए यह कदम उठाया है, लेकिन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार इस फैसले से सहमत नहीं दिख रही है। बांग्लादेश ने पीएम मोदी के इस फैसले पर हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि देश में ऐसी कोई सुरक्षा चुनौती नहीं है जिससे भारतीय अधिकारियों या उनके परिजनों को खतरा हो। बंगलादेश में हालात सभी सुरक्षित हैं। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने इस फैसले पर हैरानी जताई यूनुस सरकार ने पूछा- 'आखिर डर किस बात का?' यह सभी सुरक्षित हैं।

भारत शायद कोई संदेश देना चाहता है

तौहीद हुसैन ने इसे भारत का आंतरिक मामला बताते हुए उन्होंने यह आशंका जताई कि शायद प्रधानमंत्री मोदी इसके जरिए कोई कूटनीतिक संदेश देना चाहते है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर उन्हें सुरक्षा को लेकर कोई शिकायत नहीं मिली है।

क्या है भारत का फैसला?

12 फरवरी को बांग्लादेश में होने वाले आम चुनावों और हालिया हिंसक घटनाओं में पुजारीयों को मंदिर के अंदर जिन्दा जला दिया गया उसके बाद अन्य ह्रदयविदारक हिंसक घटनाओं को देखते हुए पीएम मोदी ने बांग्लादेश को 'नॉन-फैमिली पोस्टिंग' घोषित कर दिया है। एहतियात के तौर पर सभी राजनयिकों के परिवारों को वापस बुलाया गया है।

बांग्लादेश में हिन्दू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर मोदी सरकार की नजर

भारत सरकार ने बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस से वार्ता कर यह मुद्दा उठाया। इसके अलावा, विदेश मंत्री ने विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन के साथ बातचीत में भी इस पर चर्चा की थी कि हिन्दू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी बांग्लादेश सरकार की हैं। पीएम मोदी ने बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस से वार्ता में साफ कहा कि बांग्लादेश के सभी नागरिकों, जिनमें हिन्दू अल्पसंख्यक भी शामिल हैं, की जान-माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी बंगलादेश सरकार की है। अगर अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को निजी रंजिश या राजनीतिक कारण बताकर टाला जाता है, तो इससे अपराधियों, चरमपंथियों कट्टरपंथियों और हिन्दुओ पर हमला करने वाली विचारधारा को बढ़ावा मिलेगा और इससे हिन्दू अल्पसंख्यकों में डर और असुरक्षा का माहौल पैदा होगा।

दलित अधिकार कार्यकर्ता व वरिष्ठ अधिवक्ता रजत कल्सन ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया व राज्य बार काउंसिलों में अनुसूचित जाति वकीलों के लिए 20 प्रतिशत संवैधानिक आरक्षण की मांग की

नई दिल्ली/चंडीगढ़। दलित अधिकार कार्यकर्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रजत कल्सन ने देश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वकीलों के प्रतिनिधित्व के गंभीर संकट को उठाते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया, राज्य बार काउंसिलों तथा बार एसोसिएशनों में 20 प्रतिशत संवैधानिक आरक्षण लागू करने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल पंजाब एवं हरियाणा, भारत सरकार के कानून एवं न्याय मंत्रालय तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को एक विस्तृत कानूनी व संवैधानिक प्रतिनिधित्व (Legal Representation) भेजा है।

रजत कल्सन ने कहा कि यह एक निर्विवाद तथ्य है कि देश की अधिकांश राज्य बार काउंसिलों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय के वकीलों का प्रतिनिधित्व या तो शून्य है या नाममात्र का। विशेष रूप से बार काउंसिल पंजाब एवं हरियाणा का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि स्थापना के बाद से आज तक एक भी दलित वकील इस बार काउंसिल का निर्वाचित सदस्य, चेयरमैन या वाइस-चेयरमैन नहीं बन पाया, जो कि गंभीर संस्थागत भेदभाव को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि बार काउंसिलें Advocates Act, 1961 के तहत गठित वैधानिक संस्थाएं हैं, जो वकीलों के नामांकन, अनुशासन, विधिक शिक्षा के नियमन और वकीलों के कल्याण जैसे सार्वजनिक कार्य करती हैं। ऐसे में ये संस्थाएं संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 38 और 46 से बंधी हुई हैं और इन्हें समानता व सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य है।

रजत कल्सन ने अपने प्रतिनिधित्व में सुप्रीम कोर्ट के कई महत्वपूर्ण फैसलों का हवाला दिया है, जिनमें Indra Sawhney बनाम भारत संघ, N.M. Thomas, Jarnail Singh, B.K. Pavitra जैसे निर्णय शामिल हैं, जिनमें यह स्पष्ट किया गया है कि आरक्षण कोई अपवाद नहीं बल्कि वास्तविक समानता प्राप्त करने का संवैधानिक औजार है।

उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं वकीलों के लिए बार काउंसिलों और बार एसोसिएशनों में आरक्षण/प्रतिनिधित्व को अनिवार्य माना है, जिससे यह सिद्ध होता है कि विधिक पेशा संविधान से ऊपर नहीं है। यदि महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व संभव है, तो ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित अनुसूचित जाति समुदाय को इससे वंचित रखना घोर असंवैधानिक है।

रजत कल्सन ने मांग की कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सभी राज्य बार काउंसिलों में अनुसूचित जाति वकीलों के लिए कम से कम 20% संवैधानिक आरक्षण सुनिश्चित किया जाए।

बार एसोसिएशनों के चुनाव में रोस्टर प्रणाली लागू की जाए और हर चौथे वर्ष प्रधान व सचिव के पद अनुसूचित जाति वकीलों के लिए आरक्षित किए जाएं।

Advocates Act, 1961 और बार काउंसिल नियमों में आवश्यक संशोधन कर इस प्रतिनिधित्व को कानूनी दर्जा दिया जाए।

उन्होंने कहा कि जब संसद, विधानसभा, पंचायत और नगर निकायों में आरक्षण संवैधानिक रूप से मान्य है, तो बार काउंसिल जैसे शक्तिशाली नियामक संस्थानों को इससे बाहर रखना सामाजिक न्याय की भावना के खिलाफ है।

अंत में रजत कल्सन ने कहा कि यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि हजारों दलित वकीलों के सम्मान, भागीदारी और संवैधानिक अधिकारों की है। यदि इस दिशा में शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो दलित वकील समुदाय लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से आगे की कानूनी कार्यवाही करने को मजबूर होगा।

रजत कल्सन अधिवक्ता

परम ओंकार मंदिर में शब्द सृजन संस्था के द्वारा सरस कवि सम्मेलन 04 फरवरी को

(डॉ. गोपाल चतुर्वेदी)

मथुरा। टाउनशिप स्थिति ओंकारेश्वर कॉलोनी के परम ओंकार मंदिर में शब्द सृजन संस्था (पंजीकृत), दिल्ली एन.सी.आर. के द्वारा सरस कवि सम्मेलन 04 फरवरी 2026 को अपराह्न 03 बजे से टाउनशिप स्थित शक्तिधाम मंदिर के अधिष्ठाता आचार्यश्री पीताम्बर महाराज के पावन सानिध्य में बड़े ही हर्षोल्लास एवं धूमधाम के साथ आयोजित किया गया है। जानकारी देते हुए शब्द सृजन संस्था (पंजीकृत), दिल्ली एन.सी.आर. के संस्थापक अध्यक्ष, सुप्रसिद्ध साहित्यकार, विश्व रिकॉर्ड धारक डॉ. राजीव कुमार पाण्डेय ने बताया है कि काव्य सम्मेलन में दिल्ली, गाजियाबाद आगरा, मथुरा आदि स्थानों के श्रेष्ठ कवि गण काव्य पाठ करेंगे।जिनमें डॉ. ओंकार त्रिपाठी (दिल्ली), ₹यूपी रत्न₹ डॉ. गोपाल चतुर्वेदी (वृन्दावन), डॉ. ब्रजभूषण चतुर्वेदी (वृन्दावन), राजीव सिंघल (गाजियाबाद), गार्गी कौशिक (गाजियाबाद), रुपेश धनगर (मथुरा) व डॉ. राधाकांत शर्मा (वृन्दावन) आदि कविगण प्रमुख रूप से भाग लेंगे। कवि सम्मेलन के संयोजक डॉ. राजीव पाण्डेय ने सभी साहित्य प्रेमियों से इस सरस कवि सम्मेलन में सहभागिता करने का आग्रह किया है।

एक रंग ऐसा भी.....।

वसंत की पुरवाई में सतरंगी छटा में देशभक्ति के मधुर तराने व गीत-संगीत का दृश्य टेलीविजन पर चल रहा था। "मेरा रंग दे बसंती चोला"ङ्क, जिसे घर में बैठी बूढ़ी माँ सुन रही थी, क्योंकि उसका बेटा फौज में गया था। देशभक्ति के गाने जब भी सुनती थी, तो उस माँ की नस-नस में देशप्रेम हिलोरे ले रहा होता था।

अचानक उस घर में एकदम शांति हो गई। शांत वातावरण में जैसे ही उस माँ ने देखा तो दरवाजे पर ४-५ सैन्य जवानों के साथ उसके गौरव का धुंधला दृश्य तिरंगे में लिपटा हुआ था। वसंत के उस हवा के झोंके में उस माँ ने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर एक रंग ऐसा भी देखा। उस बेटे ने सीमा पर लड़ते हुए अपनी भारत माता के चरणों में रक्षा करते-करते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। माँ ने आँसू को रोकते हुए अपने लला को 'सैल्यूट' किया और हाथ उठाकर 'भारत माता की जय' बोलती हुई अपने दुःख को अंगीकार कर लिया।

स्वतंत्र लेखक हरिहर सिंह चौहान जबरी बाग नसिया इन्दौर

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 में आवेदन करने की संख्या को लिमिटेड नहीं किया जा सकता।

नरेश गुणपाल

माननीय ओडिशा उच्च न्यायालय ने चित्तरंजन सेठी बनाम ओडिशा राज्य सूचना आयोग एवं अन्य के मामले में याचिका संख्या 29216/2025 दिनांक-15.01.2026 न्यायमूर्ति आर.के. पटनायक की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि चाहे कोई आवेदक बड़ी संख्या में आरटीआई आवेदन क्यों न करे, उसे भविष्य में जानकारी मांगने से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने आयोग के आदेश को अवैध करार देते हुए आवेदक पर लगाए गए सभी प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटा दिए।

मुख्य तथ्यः -

एक ही विषय पर बार-बार सूचना मांगने पर भी राज्य जन सूचना अधिकारी सूचना देने से मना नहीं कर सकता।

न्यायालय ने ओडिशा सूचना पैनल द्वारा लगाए गए एक साल के आरटीआई दाखिल करने पर प्रतिबंध को रद्द कर दिया।

न्यायालय ने कहा कि सूचना निकाय के पास आरटीआई आवेदनों की संख्या सीमित करने का अधिकार नहीं है।

क्या था मामला?

ओडिशा राज्य सूचना आयोग ने सितंबर 2025 में चित्तरंजन सेठी नामक आरटीआई आवेदक को कथित रूप से "आरटीआई प्रक्रिया के दुरुपयोग"का दोषी मानते हुए एक साल के लिए नई जानकारी मांगने से रोक दिया था।

आयोग का तर्क था कि वर्ष 2023 में आवेदक ने विभिन्न विभागों में 61 से अधिक आरटीआई आवेदन दाखिल कर सार्वजनिक संसाधनों और प्रशासनिक समय की बर्बादी की है। इसके साथ ही आयोग ने यह शर्त भी लगाई थी कि आवेदक एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 12 आरटीआई आवेदन ही दे सकेगा।

मामले के तथ्यः-

याचिकाकर्ता ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी का अनुरोध किया, जिसके जवाब में याचिकाकर्ता को एक ऐसा आदेश प्राप्त हुआ जिसे याचिकाकर्ता ने अस्पष्ट और दोहरावपूर्ण बताया।

इसके बाद, लोक सूचना अधिकारी को आवेदन और उसके बाद की अपीलें प्राप्त हुईं। याचिकाकर्ता के आचरण को ध्यान में रखते हुए, ओडिशा सूचना आयोग ने उसे एक वर्ष के लिए आगे आवेदन प्रस्तुत करने से सख्ती से प्रतिबंधित कर दिया और उस अवधि के दौरान केवल 12 आवेदन दाखिल करने की अनुमति दी।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इस प्रकार के प्रतिबंध की कोई कानूनी वैधता नहीं है। मांगी

गई जानकारी और मामले के विवरण की समीक्षा करने पर, पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि सभी मांगी गई जानकारी प्रदान नहीं की गई थी।

माननीय ओडिशा उच्च न्यायालय की अहम टिप्पणियांः-

अधिकारों का हननः उच्च न्यायालय ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 संविधान और कानून से प्रदत्त नागरिक अधिकार है, जिसे प्रशासनिक आदेश से सीमित नहीं किया जा सकता।

अनुचित ढंग से पाबंदीः उच्च न्यायालय ने माना कि आवेदनों की संख्या अधिक होना, किसी नागरिक पर भविष्य की जानकारी मांगने पर रोक लगाने का आधार नहीं बन सकता।

सूचना उपलब्ध कराने का निर्देशः न्यायालय का यह भी मत है कि याचिकाकर्ता पर एक कैलेंडर वर्ष में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत कोई और आवेदन न करने की लगाई गई पाबंदी, जबकि विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों के समक्ष एक वर्ष में केवल 12 आवेदन ही दाखिल करने की अनुमति दी गई है, उचित नहीं है। दूसरे शब्दों में, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि विपक्षी पार्टी नंबर 1 याचिकाकर्ता पर ऐसी पाबंदी नहीं लगा सकती थी, भले ही वह सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मांगने वाले कई आवेदन दाखिल करने की आदत रखता हो। इसलिए, इस हद तक, अनुलग्नक-6 में उल्लिखित आदेश को रद्द किया जाना चाहिए और विपक्षी पार्टी नंबर 2 को अनुलग्नक-1 श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए शेष जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

ओडिशा उच्च न्यायालय ने माना कि ओडिशा सूचना आयोग द्वारा एक याचिकाकर्ता को प्रति वर्ष केवल 12 आरटीआई आवेदनों तक सीमित करना अनुचित था। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि आयोग किसी नागरिक द्वारा एक वर्ष में दायर किए जा सकने वाले आरटीआई आवेदनों की संख्या को सीमित नहीं कर सकता।

आरटीआई कार्यकर्ताओं में खुशी की लहरः-

15 जनवरी 2026 में आए इस फैसले का आरटीआई कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। आरटीआई कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह निर्णय सूचना के अधिकार की मूल भावना की रक्षा करेगा और अधिकारियों को मनमाने ढंग से आरटीआई आवेदनों पर रोक लगाने से रोकेगा। इसे पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

सूचना का अधिकार अधिनियम आंदोलन भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे हजारों आरटीआई कार्यकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि आयोग का निर्देश उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर था और इस हद तक, विवादित आदेश रद्द कर दिया गया।

यह फैसला याचिकाकर्ता द्वारा राज्य सूचना आयोग से अपीलों का निपटारा एक निर्धारित समय सीमा के भीतर करने का अनुरोध करने वाली याचिका के परिणामस्वरूप आया है।

नरेश गुणपाल

बढ़ती आत्महत्याओं की घटनाएं एक वैश्विक चुनौती-राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति 2030 की घोषणा- एक समग्र विश्लेषण

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी
गोंदिया महाराष्ट्र

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर मानव सभ्यता की प्रगति के साथ -साथ मानसिक,सामाजिक और आर्थिक जटिलताएँ भी बढ़ती गई हैं।इन्हीं जटिलताओं से जुड़ा एक अत्यंत गंभीर विषय है,आत्महत्या।यह केवल किसी व्यक्ति का निजी निर्णय नहीं होता,बल्कि इसके पीछे सामाजिक़ मनोवैज्ञानिक,e सांस्कृतिक और आर्थिक कारकों का गहरा प्रभाव होता है। अंतरराष्ट्रीय स्तरपर आत्महत्या को सार्वजनिक स्वास्थ्य की सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक माना जाता है।विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) के अनुसार, हर साल लगभग 7 लाख लोग आत्महत्या करके अपनी जान गंवाते हैं, जिसका अर्थ है कि हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या करता हैं। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि इससे यह स्पष्ट होता है कि यह केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं,बल्कि वैश्विक संकट है। जिसका समाधान अब अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सम्मिट बुलाकर करना समय की मांग है।बता दे भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की है।यह देश में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है जिसमें वर्ष 2030 तक आत्महत्या मृत्यु दर में 10 पर्सेंट की कमी लाने के लिये समयबद्ध कार्ययोजना और बहु-क्षेत्रीय सहयोग शामिल है।यह रणनीति आत्महत्या की रोकथाम के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र रणनीति के अनुरूप है।

साथियों बात अगर हम आत्महत्या क्या है और क्यों की जाती है? किस देश में सबसे ज्यादा आत्महत्या होती है?इसको समझने की करें तो, आत्महत्या का सामान्य अर्थ है, व्यक्ति द्वारा जानबूझकर अपनी जान लेना।यह निर्णय किसी क्षणिक आवेग का नहीं, बल्कि लंबे समय तक चले मानसिक और सामाजिक दबाव का परिणाम होता है। डब्लूएचओ की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, आत्महत्या करने वालों में से लगभग 77 पर्सेंट लोग निम्न और मध्यम आय वाले देशों से होते हैं, जहाँ मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ सीमित होती हैं और सामाजिक कलंक के कारण लोग मदद माँगने से कतराते हैं। आत्महत्या के मुख्य कारणों में डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, सिज़ोफ्रेनिया, नशे की लत, तथा सामाजिक अलगाव प्रमुख हैं। इसके अलावा रिश्तों में असफलता, बेरोजगारी, आर्थिक तंगी, घरेलू हिंसा और युवाओं पर शिक्षा व करियर का दबाव भी आत्महत्या के प्रमुख कारक हैं।वैश्विक स्तर परआत्महत्या की दर हर देश में अलग-अलग है।डब्ल्यूएचओ की 2022 की रिपोर्ट बताती है कि लिथुआनिया दक्षिण कोरिया, रूस, गुयाना और जापान जैसे देशों में प्रति 1 लाख आबादी पर आत्महत्या दर सबसे अधिक दर्ज की गई है। उदाहरण के लिए, लिथुआनिया में यह दर लगभग 25.7 प्रति 1 लाख है, जबकि दक्षिण कोरिया में लगभग 20.2 प्रति 1 लाख। वहीं भारत और चीन जैसे देशों में कुल आत्महत्याओं की संख्या सबसे अधिक है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या बहुत बड़ी है। भारत में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरब) 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, एक साल में 1.64 लाख से अधिक आत्महत्याएँ दर्ज की गईं, यानें हर दिन औसतन 450 से अधिक लोग आत्महत्या करते हैं। इनमें सबसे अधिक संख्या दैनिक वेतन बोगियों, छात्रों और किसानों की है। जापान में आत्महत्या लंबे समय से सामाजिक समस्या रही है, जहाँ हर साल लगभग 20,000 से अधिक लोग जीवन समाप्त कर लेते हैं।

साथियों बात अगर हम आत्महत्या केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक चुनौती होने की करें तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह स्वीकार किया गया है कि आत्महत्या को केवल व्यक्तिगत समस्या मानना उचित नहीं है।डब्ल्यूएचओ और अंतर्राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम संघ (आईएएसपी) के विशेषज्ञ मानते हैंकि आत्महत्या दरअसल मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों का परिणाम है।2021 में संयुक्त राष्ट्र (यूएन) द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया कि आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं के पीछे गरीबी, सामाजिक असमानता, लैंगिक भेदभाव और शिक्षा का अभाव जैसी समस्याएँ भी प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं।युवाओं में आत्महत्या की दर विशेष रूप से चिंताजनक है।15-29 वर्ष आयु वर्ग में आत्महत्या मृत्यु का चौथा सबसे बड़ा कारण है।डिजिटल युग में साइबर बुलिंग, ऑनलाइन दबाव और सोशल मीडिया की अवास्तविक अपेक्षाएँ भी युवाओं को आत्महत्या की ओर धकेल रही हैं।

साथियों बात अगर हम आत्महत्या रोकने के उपायों की करें तो शोध और डेटा संग्रह आत्महत्या रोकथाम की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है।डब्लूयुएचओ की ₹मेन्टल हेल्थ अटलस 2020₹ रिपोर्ट बताती है कि दुनियाँ के 80 पर्सेंट से अधिक देशों में आत्महत्या से संबंधित डेटा उपलब्ध नहीं है या अधूरा है। इससे नीतियों का निर्माण कठिन हो जाता है। आईएएसपी लगातार इस दिशा में अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा दे रहा है। अमेरिका और यूरोप के देशों ने आत्महत्या रोकथाम पर व्यापक शोध कियाe है, जिससे यह साबित हुआ है कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (सीबीटी), साइकोसोशल सपोर्ट, हेल्पलाइन सेवाएँ और सामुदायिक सहयोग आत्महत्या रोकने में बहुत प्रभावी हैं।पेशेवरों को प्रशिक्षित करना भी इस दिशा में अत्यंत आवश्यक है डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार, दुनियाँ भर में प्रति 1 लाख लोगों पर औसतन केवल 13 मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर हैं, जबकि विकसित देशों में यह अनुपात बहुत अधिक है। इस असमानता के कारण निम्न और मध्यम आय वाले देशों में आत्महत्या रोकथाम चुनौतीपूर्ण बन जाती है। यदि डॉक्टर, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और पुलिसकर्मी आत्महत्या के संकेतों को पहचानने और सही समय पर हस्तक्षेप करने में प्रशिक्षित हों, तो कई जिंदगियाँ बचाई जा सकती हैं।

साथियों बात अगर हम आत्महत्याओं को रोकने के लिए शिक्षा और संवाद की आवश्यकता सबसे मजबूत हथियार होने की करें तो, आईएएसपी और डब्लूयुएचओ दोनों ही यह मानते हैं कि सार्वजनिक जागरूकता से आत्महत्या की प्रवृत्ति को काफी हद तक कम किया जा सकता है। डब्लूयुएचओ की 2022 की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि मानसिक स्वास्थ्य पर संवाद बढ़ाने से आत्महत्या दर में 20 पर्सेंट तक की कमी लाई जा सकती है।आज भी अधिकांश समाजों में मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या को लेकर सामाजिक कलंक मौजूद है। लोग इस विषय पर बात करने से कतराते हैं।इसका परिणाम यह होता है कि पीड़ित व्यक्ति अकेलेपन और शर्मिंदगी का शिकार हो जाता है। युवाओं के बीच संवाद को बढ़ावा देना और उन्हें यह समझाना कि मदद माँगना कमजोरी नहीं बल्कि साहस है, अत्यंत आवश्यक है। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में काउंसलिंग सेवाएँ, हेल्पलाइन नंबर, मानसिक स्वास्थ्य कार्यशालाएँ शुरू करना उपयोगी साबित हो सकता है। उदाहरण के लिए, दक्षिण कोरिया और जापान ने स्कूल स्तरपरमानसिक स्वास्थ्य शिक्षा लागू की है, जिससे आत्महत्या की दर कम करने में मदद मिली है।

साथियों बात अगर हम आत्महत्या की रोकथाम के वैज्ञानिक और सामाजिक उपायों की करें तो, आत्महत्या रोकथाम के लिए बहुआयामी उपाय आवश्यक हैं।डब्लूयुएचओ की ₹लाइव लाइफ₹ रणनीति (2021) में चार प्रमुख उपाय सुझाए गए हैं (1) हानिकारक साधनों की उपलब्धता को कम करना (जैसे कीटनाशक, आग्नेयास्त्र, दवाइयाँ), (2) मीडिया रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार दिशानिर्देश बनाना, (3) किशोरों और युवाओं में सामाजिक व भावनात्मक कौशल विकसित करना, (4) जल्दी पहचान और सहायता उपलब्ध कराना।इन उपायों से आत्महत्या की दर में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है। उदाहरण के लिए, श्रीलंका ने कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाकर आत्महत्या की दर को 70 पर्सेंट तक घटा दिया। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने हेल्पलाइन और काउंसलिंग सेवाओं का विस्तार करके आत्महत्या रोकथाम में सफलता प्राप्त की हैं।

एक सीमित दुनिया से असीमित कल्पना तक: बाल-पठन संस्कृति का संकट

डॉ. विजय गर्ग

संपादकीय

चिंतन-मनन

यह पढ़ने को त्वरित हिट्स की एक सीमित दुनिया तक सीमित कर देता है, न कि कथा और कल्पना द्वारा प्रस्तुत असीमित संभावनाओं में गहराई से उतरने तक। परिणामस्वरूप, बच्चों को उच्च स्तरीय साक्षरता कौशल विकसित करने में कठिनाई हो सकती है, जैसे अनुमानात्मक तर्क, सहानुभूति और आलोचनात्मक सोच - ये सभी समय के साथ समृद्ध साहित्यिक सहभागिता के माध्यम से पनपते हैं।

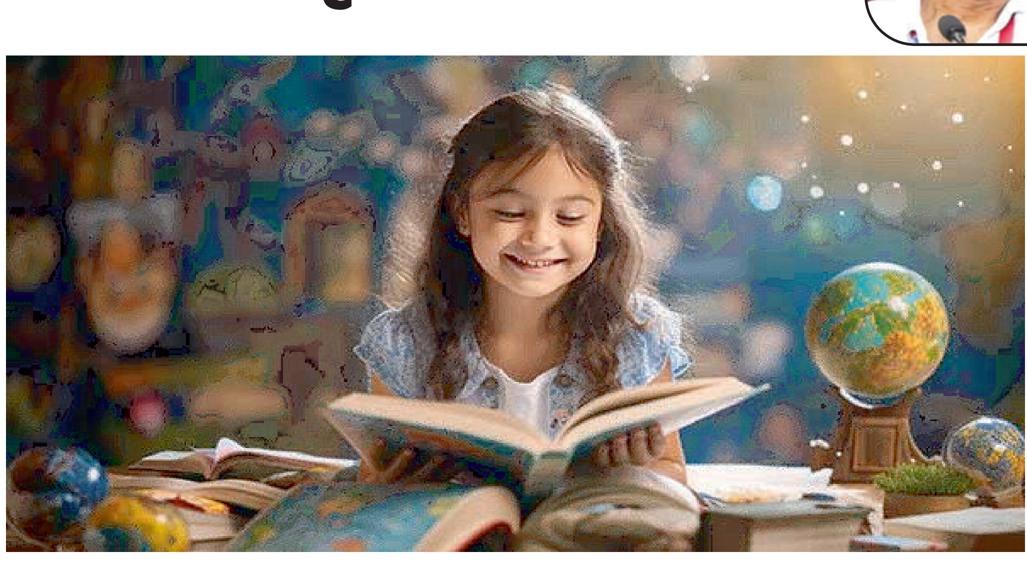

डिजिटल उपकरणों, खंडित ध्यान और तीव्र सूचना प्रवाह के युग में, बच्चों की पठन संस्कृति को एक गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। कभी पुस्तकों के साथ धीमी, गहन सहभागिता में निहित बचपन की पढ़ाई अब लघु डिजिटल सामग्री की अंतहीन धाराओं से प्रतिस्पर्धा करती है। यह बदलाव केवल इस बारे में नहीं है कि बच्चे क्या पढ़ते हैं, बल्कि इस बारे में भी है कि वे — कैसे पढ़ते हैं और उनकी कल्पना, संज्ञानात्मक विकास और सांस्कृतिक भागीदारी के लिए इसका क्या अर्थ है।

खंडित ध्यान की अंतिम दुनिया

आधुनिक डिजिटल वातावरण इस बात को आकार देता है कि युवा पाठक पाठ के साथ किस प्रकार बातचीत करते हैं। स्क्रीन पर निरंतर उत्तेजना, हाइपरलिंक, वीडियो और सूचनाएं दिखाई देती हैं, जो ध्यान को विभाजित करती हैं तथा गहन पढ़ने के बजाय स्किमिंग को प्रोत्साहित करती हैं। शोधकर्ताओं ने पाया है कि डिजिटल पहुंच युवाओं के लिए सामग्री की एक विशाल श्रृंखला को तुरंत उपलब्ध कराती है, लेकिन यह ध्यान भटकाने और कम समय तक ध्यान देने में भी सहायक होती है - जिससे कहानियों और जटिल विचारों के साथ निरंतर जुड़ाव का विकास बाधित होता है। यह पढ़ने को त्वरित हिट्स की एक सीमित दुनिया तक सीमित कर देता है, न कि कथा और कल्पना द्वारा प्रस्तुत असीमित संभावनाओं में गहराई से उतरने तक। परिणामस्वरूप, बच्चों को उच्च स्तरीय साक्षरता कौशल विकसित करने में कठिनाई हो सकती है, जैसे अनुमानात्मक तर्क, सहानुभूति और आलोचनात्मक सोच - ये सभी समय के साथ समृद्ध साहित्यिक सहभागिता के माध्यम से पनपते हैं।

कल्पना क्यों मायने रखती है

कथा साहित्य पढ़ना शब्दावली या समझ सिखाने से कहीं अधिक काम करता है। यह उन दुनियाओं के लिए दरवाजे खोलता है जो जीवित अनुभव से परे हैं, कल्पना को बढ़ावा देते हैं - मानसिक स्थान जहां बच्चे वैकल्पिक वास्तविकताओं का पता लगा सकते हैं, भावनाओं पर विचार कर सकते हैं, और अन्य लोगों के दिमाग को समझ सकते हैं। जब बच्चे पढ़ते हैं, तो वे अपने मन में सक्रिय रूप से दुनिया का निर्माण करते हैं, जिससे उनकी रचनात्मकता और सहानुभूति की क्षमता समृद्ध होती है, जिसे निष्क्रिय मीडिया शायद ही कभी प्राप्त कर पाता है।

कल्पना एक तुच्छ कौशल नहीं है: यह नवाचार, कथात्मक समझ और जटिल नैतिक स्थितियों से निपटने की क्षमता को बढ़ावा देता है - जिसे 21वीं सदी में तेजी से आवश्यक माना जा रहा है। इसके बिना, शिक्षा तथ्यों को याद करने का एक बाँझ अभ्यास बन सकती है, तथा कहानियों में मौजूद परिवर्तनकारी शक्ति खो सकती है।

पठन संस्कृति का पतन

पठन संस्कृति में संकट कई तरीकों से प्रकट होता है:

प्रेरणा हानि (साक्षरता)

कई बच्चे पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा करना पसंद नहीं करते। यह स्थिति, जिसे साक्षरता के रूप में जाना जाता है, पढ़ने की प्रेरणा में गिरावट को दर्शाता है, यहां तक कि जहां साक्षरता कौशल मौजूद हैं।

डिजिटल विस्थापन

डिजिटल मीडिया अक्सर पारंपरिक पठन को त्वरित उपभोग के साथ प्रतिस्थापित कर देता है, जिससे पाठ के साथ विस्तारित कल्पनाशील जुड़ाव के अवसर कम हो जाते हैं। ऐप्स और सामग्री के बीच स्विच करने में आसानी से गहन पढ़ाई कठिन हो जाती है और यह कम आदत बन जाती है।

शैक्षिक दबाव

कुछ शैक्षिक प्रणालियाँ अनुभवात्मक पठन की अपेक्षा मापनीय परिणामों और परीक्षण पर जोर देती हैं। जब पाठ्यक्रम मानकीकृत मूल्यांकन को प्राथमिकता देता है, तो आश्चर्य और रचनात्मकता को प्रेरित करने वाली पुस्तकें किनारे हो जाती हैं।

पहुंच और इक्विटी चुनौतियां

दुनिया के कई हिस्सों में, बच्चों को अभी भी विभिन्न प्रकार की पठन सामग्री और सहायक पठन वातावरण तक पहुंच का अभाव है, जिससे संकट कम होने के बजाय उसे बढ़ाया जा रहा है।

पठन परिवर्तनकारी शक्ति इन चुनौतियों के बावजूद, शोध से पता चलता है कि पढ़ना क्यों महत्वपूर्ण बना हुआ है कथा साहित्य पढ़ने से सहानुभूति, आलोचनात्मक सोच और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ावा मिलता है। पढ़ना बच्चों के विश्वदृष्टिकोण को व्यापक बनाता है, तथा उन्हें अपने तात्कालिक वातावरण से परे दृष्टिकोण और संस्कृतियों का पता लगाने में मदद करता है। निरंतर पढ़ने से भाषा दक्षता बढ़ती है और संज्ञानात्मक कौशल मजबूत होता है जो वयस्कता में भी जारी रहता है।

संकट के समय - चाहे शैक्षिक व्यवधान हो, वैश्विक अस्थिरता हो, या तीव्र सामाजिक परिवर्तन हो - पठन एक लंगर के रूप में कार्य करता है जो सीखने की निरंतरता को संरक्षित करता है और युवा शिक्षार्थियों के लिए भावनात्मक स्थिरता प्रदान करता है।

संकट से लेकर रचनात्मक संभावनाओं तक

बच्चों द्वारा पढ़ी जाने वाली संस्कृति के संकट से आगे बढ़ने के लिए, हमें पढ़ने के सीमित दृष्टिकोण - जो स्कूल के कार्यों या डिजिटल ब्लिप्स तक ही सीमित है - को असीमित कल्पना अभिविन्यास की ओर ले जाना चाहिए, जो पुस्तकों को आश्चर्य, जिज्ञासा और आत्म-अभिव्यक्ति के स्थान के रूप में महत्व देता है।

क्या किया जा सकता है?

आनंद के लिए पढ़ने का अभ्यास करें: बच्चों को केवल वयस्कों द्वारा दी गई पुस्तकों की बजाय, उनकी जिज्ञासा को जगाने वाली पुस्तकें चुनने के लिए प्रोत्साहित करें।

विविध साहित्य को एकीकृत करें: विभिन्न संस्कृतियों और विधाओं की कहानियां प्रदान करें, जिससे बच्चों के कल्पनाशील क्षितिज का विस्तार हो।

प्रौद्योगिकी और गहन पठन को संतुलित करें: इमर्सिव साहित्यिक अनुभवों को बदलने के बजाय उन्हें बढ़ाने के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग करें।

पुस्तकों तक पहुंच का समर्थन करें: पुस्तकालय, सामुदायिक कार्यक्रम और पारिवारिक पठन समय पढ़ने की संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

निष्कर्ष

बच्चों के पढ़ने की संस्कृति में संकट केवल साक्षरता दरों में गिरावट के बारे में नहीं है; यह बच्चों के जीवन में कल्पना के लिए कम होते स्थान के बारे में भी है। इस संकट से आगे बढ़ने के लिए ऐसे परिवेश की आवश्यकता है जहां कहानियों को जिया जाए, काल्पनिक दुनिया का अन्वेषण किया जाए, और पढ़ना एक आनंदमय, असीम यात्रा बन जाए। एक ऐसी संस्कृति जो कल्पना को महत्व देती है, बच्चों को न केवल तेजी से जटिल होती दुनिया में आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है, बल्कि सपने देखने, प्रश्न करने और उसे बदलने के लिए भी तैयार करती है।

गहन साक्षरता का क्षरण बाल-पठन संस्कृति का संकट भी ध्यान देने का संकट है। डिजिटल वातावरण को ₹स्किमिंग और स्कैनिंग₹ के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह डेटा बाढ़ में नेविगेट करने के लिए एक जीवित रहने की प्रणाली है। हालाँकि, गहन पठन के लिए रैखिक ध्यान और धैर्य की आवश्यकता होती है। रैखिक सोच: पुस्तकें निरंतर कथात्मक चापों के माध्यम से कारण और प्रभाव सिखाती हैं। सहानुभूति विकास: साहित्य बच्चों को एक पात्र के आंतरिक एकालाप में रहने की अनुमति देता है, जिससे सहानुभूति की गहराई पैदा होती है जिसे 15 सेकंड की क्लिप से अनुकरण नहीं किया जा सकता। शब्दावली विस्तार: लिखित पाठ में आमतौर पर संवादात्मक भाषण या टेलीविजन स्क्रिप्ट की तुलना में कहीं अधिक विविध शब्दकोश का उपयोग किया जाता है। ₹अंतिम विश्व₹ क्यों जीत रहा है पढ़ने में गिरावट शून्य में नहीं हो रही है। कई सांस्कृतिक तनाव इस बदलाव को तेज कर रहे हैं: एल्गोरिदम की सुविधा: डिजिटल प्लेटफॉर्म को ₹घर्षण₹ को दूर करने के लिए इंजीनियर किया गया है पढ़ना, जिसके लिए मानसिक प्रयास की आवश्यकता होती है, अक्सर स्वचालित फीड की सहजता के कारण असफल हो जाता है। बोरियत की मृत्यु: कल्पना ₹कुछ न करने₹ के अंतराल में पनपती है आज, हर खाली सेकंड डिजिटल शोर से भरा हुआ है, जिससे बच्चे के पास जिज्ञासावश किताब उठाने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। प्रदर्शनात्मक पालन-पोषण: उच्च दबाव वाली दुनिया में, माता-पिता अक्सर शांत पढ़ने के समय होने वाले ₹अदृश्य₹ विकास की तुलना में ₹माप योग्य₹ कौशल (कोडिंग, खेल, ग्रेड) को प्राथमिकता देते हैं। असीमित को पुनः प्राप्त करना इस संकट को हल करने के लिए, हमें पढ़ने को एक काम या स्कूल असाइनमेंट के रूप में देखना बंद कर देना चाहिए और इसे स्वतंत्रता का विध्वंसकारी कार्य मानने लगना चाहिए। > एलन बेनेट ने लिखा, ₹पुस्तक कल्पना को प्रज्वलित करने का एक उपकरण है।₹ यदि हम उस लौ को बुझने दें, तो हमें एक ऐसी पीढ़ी पैदा करने का जोखिम उठाना पड़ेगा जो स्क्रीन पर पूरी तरह से काम कर सकती है, लेकिन वर्तमान में दिखाई जा रही दुनिया से बेहतर दुनिया की कल्पना नहीं कर सकती। सीमित से असीमित में परिवर्तन के लिए, हमें बच्चों को ऊबने की जगह प्रदान करनी चाहिए, उन्हें अपनी कहानियां स्वयं चुनने की अनुमति देनी चाहिए, तथा वयस्कों का उदाहरण देना चाहिए जो अभी भी पुस्तक के कवरों के बीच जादू पाते हैं।

सेवानिवृत्त प्रधान शैक्षिक स्तंभकार प्रख्यात शिक्षाविद स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब

स्थापना दिवस 1 फरवरी : भारतीय तटरक्षक बल : समुद्री सीमा पर सन्नद्ध-सजग प्रहरी

प्रमोद दीक्षित मलय

लगभग पांच दशक पहले जब मैं एक कस्बे में रहकर प्रारम्भिक शिक्षा ग्रहण कर रहा था, तब कक्षा में एक छात्र इलेक्ट्रानिक घड़ी और खिलौने लेकर आया करता था। वे शायद जापान में बने थे और चोरी-छिपे भारतीय चोर बाजारों में पहुंचाया जाता था, जहां से अमीर और शौकिया लोग महंगे दामों पर खरीदते थे। तब उस तरह का सामान खुले बाजार में वहां उपलब्ध नहीं था, तो सभी की पहुंच में भी नहीं था। कक्षा में अन्य सभी बच्चे उसे घेरे रहते और उसके नखरे उठाते, पढ़ाई-लिखाई में कुछ मदद भी करते। उसकी घड़ी पूरे स्कूल में कौतूहल का केंद्र हुआ करती। सभी बच्चे उसमें दिन, दिनांक, समय आदि बटन दबा-दबा कर देखते, मैंने भी देखा था। बहुत बाद में पता चला कि ऐसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और सोना समुद्र के रास्ते तस्करी करके लाया जाता है क्योंकि तब समुद्री रास्तों और तटीय क्षेत्रों में समुचित निगरानी के प्रबंध का अभाव था। मादक पदार्थों, सोना, समुद्री जीव-जंतुओं और अन्य वस्तुओं की बड़े पैमाने पर हो रही तस्करी को रोकने, समुद्री हितों की रक्षा करने, समुद्री कानूनों को लागू करने, तटीय सुरक्षा सुनिश्चित करने, समुद्री पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करने, खतरे में पड़े पोतों व नौकाओं का बचाव कार्य करने तथा समुद्री आपदा के समय अविलम्ब सहायता उपलब्ध कराने हेतु के.एफ. रुस्तम जी की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश पर नौ सेना से प्राप्त कुछ विमान, नौकाओं एवं अन्य संसाधनों के साथ 1 फरवरी, 1977 को भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना की गयी थी, जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। बाद में संसद में पारित तटरक्षक बल अधिनियम 1978 के द्वारा 18 अगस्त, 1978 को भारतीय तटरक्षक बल का विधिवत उद्घघाटन किया गया था। किंतु भारतीय तटरक्षक बल अपनी वर्षगांठ 1 फरवरी को ही मनाता है। इस अवसर पर उत्कृष्ट योगदान देने वाले सैनिकों एवं अधिकारियों को सेवा मैडल प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि भारतीय तटरक्षक बल आज अत्याधुनिक पोतों, गस्ती नौकाओं, विमानों, राडार आदि खोजी यंत्रों एवं समर्पित ध्येयनिष्ठ सैनिकों की संख्या के आधार पर विश्व का चौथा सबसे बड़ा तटरक्षक बल बन चुका है। भारतीय तटरक्षक बल का आदर्श वाक्य है - वयं रक्षामः अर्थात हम रक्षा करते हैं जो बल की कर्तव्यनिष्ठा, सतर्कता एवं स्वाभिमानी गरिमामय छवि का परिचायक है।

किसी भी देश के आंतरिक एवं बाहरी खतरों एवं चुनौतियों से निबटने के लिए सैन्य या अर्धसैन्य बल महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करते हैं। यह देश की सम्प्रभुता, अखंडता एवं सतत विकास के लिए आवश्यक होता है। भारत के संदर्भ में जमीनी सीमा के साथ समुद्री सीमा की सुरक्षा करते हुए देश में शांति, सुरक्षा एवं विकास का वातावरण बनाये रखने की एक बड़ी जिम्मेदारी स्वाभाविक है। भारत भूमि तीन ओर से समुद्र से घिरी है। पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर तथा सैकड़ों की संख्या में द्वीप। वर्ष 2025 में माप अनुसार भारत की समुद्री सीमा लगभग 11-12 हजार किमी है, जिसमें मुख्य भूमि तट 5422 किमी तथा द्वीपीय तट 7516 किमी है, पर इनमें आंशिक बदलाव होता रहता है। भारत की क्षेत्रीय समुद्र जल सीमा 12 समुद्री मील अर्थात 22 किमी से कुछ अधिक है। भारत के समुद्री तट 9 राज्यों - गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिसा, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक एवं गोवा तथा 4 केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करते हैं। सबसे बड़ी समुद्री तट रेखा गुजरात की है जो 2340 किमी है, जबकि गोवा की सबसे कम। भारतीय तटरक्षक बल अपनी सम्पूर्ण शक्ति एवं सामर्थ्य के साथ समुद्री तटों की निगरानी करते हुए समुद्री क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के लिए भी बद्धपरिकर रहता है। तेल टैंकरों से तेल रिसाव, नाविकों को सहायता, मत्स्य एवं खनिज के उचित दोहन में मदद, समुद्री जीवन पर वैज्ञानिक शोध एवं आंकड़े तथा संकट में मानवीय सहायता उपलब्ध कराना भारतीय तटरक्षक बल की प्रमुख भूमिकाएं हैं। भारतीय तटरक्षक बल के सेवा क्षेत्र को पांच क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जिसके मुख्यालय मुम्बई, चैन्नै, गांधीनगर, पोर्ट ब्लेयर एवं कोलकाता में हैं। समन्वय हेतु मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

भारतीय तटरक्षक बल देश का गौरव है। वह सदैव समुद्र तटों की सुरक्षा करते हुए मादक पदार्थों, हथियारों, सोना, जीव-जंतुओं की तस्करी पर लगाम लगाने एवं अवैध मानव आव्रजन की रोकथाम कर देश में सुरक्षित परिवेश बनाने में सफल हुआ है। युद्ध के समय नौ सेना की मदद कर उसकी शक्ति में वृद्धि कर देता है। कह सकते हैं, भारतीय तटरक्षक बल समुद्री तटों पर सन्नद्ध एवं सजग होकर अपने कर्तव्य पालन में जुटे हुए हैं तभी हम देशवासी अपने-अपने कार्यों को शांति एवं सुगमता के साथ करते हुए देश के विकास में योगदान कर रहे हैं। भारतीय तटरक्षक बल की यशगाथा अनवरत ऊर्ध्वगामी हो, उसकी शौर्य पताका पराक्रम के आकाश पर फहरती रहे, यही कामना है।

यूरोप की साझा राजनीति : यूरोपीय संघ

विवेक रंजन श्रीवास्तव

भारत के साथ ट्रेड डील से EU चर्चा में है। यूरोपीय संघ केवल देशों का समूह नहीं है, वह इतिहास की प्रयोगशाला है जहाँ सदियों की लड़ाइयों, साम्राज्यों के उत्थान पतन और सीमाओं के खून से खिंचे नक्शों के बाद यह तय किया गया कि अब तलवार नहीं, समझौता चलेगा। द्वितीय विश्व युद्ध के मलबे से उठकर यूरोप ने यह स्वीकार किया कि राष्ट्रवाद की अति अंततः राष्ट्रों को ही लहूलुहान करती है। इसी स्वीकारोक्ति से जन्म हुआ यूरोपीय संघ का जो आज दुनिया की सबसे संगठित और जटिल बहुराष्ट्रीय संरचनाओं में से एक है।

वर्तमान यूरोपीय संघ में सत्ताईस देश शामिल हैं। जर्मनी और फ्रांस इसकी धुरी माने जाते हैं तो इटली और स्पेन इसकी ऐतिहासिक आत्मा हैं। नीदरलैंड, बेल्जियम और लक्जमबर्ग जैसे छोटे देश इसके प्रशासनिक संतुलन को साधते हैं। पूर्वी यूरोप से पोलैंड, हंगरी, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, रोमानिया और बुल्गारिया जैसे देश इसके विस्तार का प्रतीक हैं। बाल्टिक क्षेत्र के एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया इसकी रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करते हैं। साइप्रस और माल्टा भूमध्य सागर की आवाज हैं जबकि स्कैंडिनेवियाई स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क इसकी सामाजिक चेतना को आकार देते हैं। ब्रिटेन कभी इसका हिस्सा था पर ब्रेक्जिट ने यह सिखा दिया कि संघ में रहना भी एक राजनीतिक धैर्य की मांग करता है।

यूरोपीय संघ की कोई एक राजधानी नहीं है और यही उसकी खासियत भी है। यह सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित करने के बजाय उसे फैलाकर संतुलित करता है। ब्रसेल्स इसका प्रशासनिक चेहरा है जहाँ से नीतियां बनती हैं और फाइलें चलती हैं। स्ट्रासबर्ग लोकतांत्रिक मंच है जहाँ यूरोपीय संसद की बहसें गूंजती हैं। लक्जमबर्ग न्यायिक विवेक का केंद्र है जहाँ कानूनों की आत्मा को परखा जाता है। यह बिखराव दरअसल शक्ति के विकेंद्रीकरण का प्रतीक है जो यूरोपीय संघ की मूल भावना से मेल खाता है।

मुद्रा के स्तर पर यूरोपीय संघ ने साहसिक कदम उठाया। यूरो नामक साझा मुद्रा को अपनाकर कई देशों ने अपनी सदियों पुरानी राष्ट्रीय मुद्राओं को इतिहास में दर्ज कर दिया। यह केवल नोट और सिक्के बदलने का मामला नहीं था, यह आर्थिक संप्रभुता का साझा प्रयोग था हालांकि सभी सदस्य देशों ने यूरो को नहीं अपनाया है। कुछ देशों ने अपनी मुद्रा बनाए रखी है ताकि आर्थिक नीतियों पर उनका सीधा नियंत्रण बना रहे। यूरोपीय केंद्रीय बैंक फ्रैंकफर्ट से इस साझा मुद्रा की नब्ज थामे बैठा है और पूरे महाद्वीप की आर्थिक धड़कन को संतुलित रखने की कोशिश करता है।

लोकतंत्र की दृष्टि से यूरोपीय संघ एक दिलचस्प संरचना है। यहां नागरिक केवल अपने देश की सरकार नहीं चुनते बल्कि एक महाद्वीपीय संसद के प्रतिनिधि भी चुनते हैं। हर पांच वर्ष में होने वाले यूरोपीय संसद के चुनाव इस बात का संकेत हैं कि नागरिकों की आवाज राष्ट्रीय सीमाओं से आगे जाकर सुनी जाती है। हालांकि अक्सर यह भी देखा गया है कि आम नागरिक यूरोपीय चुनावों को राष्ट्रीय राजनीति की कसौटी पर ही तौलता है जिससे संघ और जनता के बीच दूरी की बहस जन्म लेती है।

प्रशासनिक ढांचे में यूरोपीय संघ एक संतुलन साधने की निरंतर कोशिश है। यूरोपीय आयोग प्रस्ताव लाता है, यूरोपीय परिषद दिशा तय करती है, संसद बहस और संशोधन करती है और न्यायालय अंतिम व्याख्या करता है। यह प्रक्रिया धीमी लग सकती है, पर यही इसकी मजबूती भी है। जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से यूरोप पहले ही बहुत कुछ खो चुका है, इसलिए यहां निर्णय समय लेते हैं पर सोच समझकर लिए जाते हैं।

अंततः यूरोपीय संघ एक राजनीतिक व्यवस्था से अधिक एक विचार है। यह विचार कि विविध भाषाएं, संस्कृतियां और राष्ट्रीय स्वार्थ एक साझा मंच पर रह सकते हैं। यह प्रयोग पूरी तरह सफल है या नहीं, यह बहस का विषय हो सकता है पर इतना तय है कि यूरोपीय संघ ने दुनिया को यह दिखाया है कि शक्ति केवल सैन्य या आर्थिक नहीं होती बल्कि सहयोग और सहमति भी एक बड़ी ताकत हो सकती है। शायद इसी कारण यूरोपीय संघ आज भी विश्व राजनीति में एक शांत लेकिन प्रभावशाली उपस्थिति बना हुआ है।

गुरु रविदास जयंती: सामाजिक समता और मानवीय गरिमा के महान उद्घोषक

बाबूलाल नागा

गुरु रविदास जयंती हिंदू चंद्र पंचांग के माघ महीने की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। यह आमतौर पर हर साल जनवरी या फरवरी में पड़ती है। 2026 में गुरु रविदास जयंती रविवार, 1 फरवरी को मनाई जाएगी। गुरु रविदास जयंती एक विशेष अवसर है जो 15वीं शताब्दी के संत, कवि और समाज सुधारक गुरु रविदास के जन्मदिवस को चिह्नित करता है। वे एक आध्यात्मिक नेता थे जिन्होंने समानता, एकता और ईश्वर के प्रति भक्ति का संदेश फैलाया। उनकी शिक्षाओं ने लोगों को जातिगत भेदभाव से उबरने और प्रेम, विनम्रता और धर्म का अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया।

भारत की संत परंपरा में गुरु रविदास का नाम सामाजिक समता, मानव गरिमा और आध्यात्मिक चेतना के सशक्त प्रतीक के रूप में दर्ज है। गुरु रविदास जयंती केवल एक महापुरुष की स्मृति का अवसर नहीं, बल्कि उस वैचारिक विरासत को दोहराने का दिन है जिसने सदियों पहले जाति, ऊंच-नीच और भेदभाव की जड़ों पर सीधा प्रहार किया। मध्यकालीन भारत में जब समाज कठोर जाति-व्यवस्था और सामाजिक असमानताओं से जकड़ा हुआ था, तब गुरु रविदास ने अपने जीवन, कर्म और वाणी से समानता और मानवता का संदेश दिया।

गुरु रविदास का जन्म काशी (वर्तमान वाराणसी) में हुआ माना जाता है। उनका जीवन एक साधारण श्रमिक समुदाय से जुड़ा रहा, लेकिन उनकी सोच और चेतना असाधारण थी। उन्होंने यह

सिद्ध किया कि आध्यात्मिक ऊंचाई किसी जाति, वर्ग या पेशे की मोहताज नहीं होती। उनके लिए मनुष्य की पहचान उसके कर्म, आचरण और मानवीय मूल्यों से थी, न कि जन्म से मिली सामाजिक श्रेणी से।

गुरु रविदास के सामाजिक योगदान का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष जाति-व्यवस्था का विरोध है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सभी मनुष्य ईश्वर की संतान हैं और उनमें कोई भेद नहीं किया जा सकता। उनके भजनों और पदों में यह संदेश बार-बार उभरता है कि ईश्वर न मंदिरों की दीवारों में सीमित है और न ही किसी एक वर्ग का विशेषाधिकार है। उनके अनुसार सच्ची भक्ति वही है जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ती है, न कि तोड़ती है।

उनकी वाणी ने श्रमिकों, शोषितों और वंचितों को आत्मसम्मान दिया। उस समय समाज के निचले पायदान पर रखे गए समुदायों को गुरु रविदास ने यह विश्वास दिलाया कि वे भी ज्ञान, भक्ति और मुक्ति के अधिकारी हैं। यह एक क्रांतिकारी विचार था, जिसने सामाजिक चेतना को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने अपने जीवन से यह उदाहरण प्रस्तुत किया कि श्रम कोई हीन कार्य नहीं, बल्कि ईमानदार श्रम स्वयं में पूजनीय है।

गुरु रविदास का "बेगमपुरा" का विचार भारतीय सामाजिक चिंतन में एक अद्वितीय कल्पना है। बेगमपुरा—अर्थात ऐसा समाज जहां कोई दुःख न हो, कोई भेदभाव न हो, कोई कर या अन्याय न हो—एक समतामूलक समाज का स्वप्न था। यह केवल आध्यात्मिक कल्पना नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की स्पष्ट अवधारणा थी। आज के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों में भी इस विचार की गूंज सुनाई देती है।

भक्ति आंदोलन में गुरु रविदास का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने भक्ति को कर्मकांडों से मुक्त कर जनसामान्य की भाषा और अनुभव से जोड़ा। उनकी वाणी सरल, सहज और जीवन से जुड़ी हुई थी। यही कारण है कि उनका प्रभाव केवल धार्मिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सामाजिक सुधार के आंदोलन में भी दिखाई देता है। गुरु ग्रंथ साहिब में उनके पदों का समावेश इस बात का प्रमाण है कि उनकी वाणी ने धार्मिक सीमाओं से ऊपर उठकर मानवता को जोड़ा।

गुरु रविदास ने सामाजिक संवाद में प्रेम, करुणा और सह-अस्तित्व को केंद्रीय स्थान दिया। उन्होंने न तो हिंसा का मार्ग अपनाया और न ही कटुता का। उनकी क्रांति शांति, विचार और आत्मबोध की क्रांति थी। यही कारण है कि उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं, जब समाज फिर से विभाजन और असमानता की चुनौतियों से जूझ रहा है।

आज गुरु रविदास जयंती पर उनके विचारों को स्मरण करना केवल औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। यह अवसर है आत्ममंथन का—कि क्या हमारा समाज उस बेगमपुरा की ओर बढ़ रहा है, जिसकी कल्पना उन्होंने की थी? क्या हम आज भी जाति, वर्ग और पहचान के नाम पर मनुष्य को बांट रहे हैं, या गुरु रविदास के समानता और न्याय के संदेश को जीवन में उतार रहे हैं?

गुरु रविदास का जीवन हमें सिखाता है कि सामाजिक परिवर्तन केवल सत्ता या कानून से नहीं, बल्कि चेतना के परिवर्तन से आता है। उन्होंने बिना किसी पद या शक्ति के, केवल अपने विचारों से समाज की दिशा को प्रभावित किया। यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है।

गुरु रविदास जयंती पर यह संकल्प लेना आवश्यक है कि हम उनके बताए मार्ग पर चलते हुए एक ऐसे समाज के निर्माण में योगदान दें, जहां हर व्यक्ति को सम्मान, समान अवसर और मानवीय गरिमा प्राप्त हो। यही गुरु रविदास को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

माखनलाल चतुर्वेदी : राष्ट्रीय पत्रकारिता का तेजोमय प्रखर स्वर

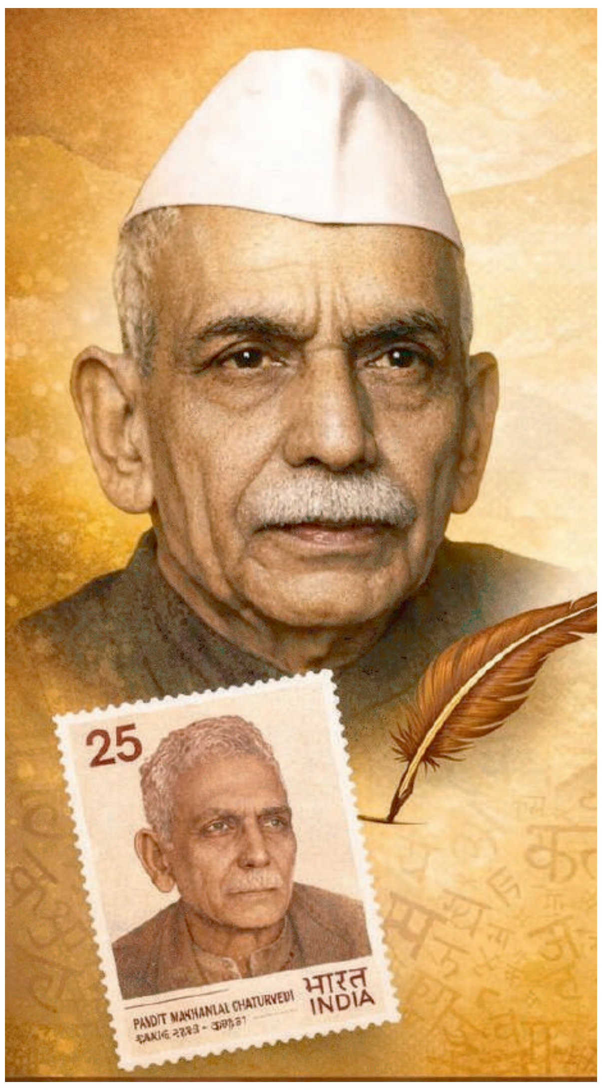

प्रमोद दीक्षित मलय

प्राथमिक शिक्षा के दौरान एक कविता पढ़ने को मिली थी जिसका प्रेरक भाव मन-मस्तिष्क में आज भी अंकित है। न केवल वह कविता आज तक कंठस्थ है बल्कि वह महनीय रचनाकार का व्यक्तित्व और जीवन भी आंखों के सम्मुख चलचित्र की भांति वर्तमान है। वह कविता थी - 'चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं.... मुझे तोड़ लेना वनमाली, देना उस पथ पर तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर जावें वीर अनेक। और रचनाकार हैं राष्ट्रवादी पत्रकारिता के शिखर पुरुष ओजस्वी वक्ता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माखनलाल चतुर्वेदी। 30 जनवरी को देश पुण्यतिथि के अवसर पर उस महान संपादक और देश में पत्रकारिता के विद्यापीठ के स्वप्नकार के प्रति श्रद्धा सुमन समर्पित कर स्वयं गौरवांवित है।

माखनलाल चतुर्वेदी भारतीय पत्रकारिता आकाश के उज्ज्वल नक्षत्र हैं। उनका विराट व्यक्तित्व विभिन्न छवियों के साथ लोक सम्मुख प्रकट होता है। एक ओर वह शिक्षण परम्परा को गति देते दिखाई पड़ते हैं तो वहीं दूसरी ओर उनका साहित्यकार रूप हमें सम्मोहित करता है। वह जितनी भाव प्रवणता, करुणा, प्रेम एवं संवेदनशीलता के साथ काव्य कला के क्षेत्र में विचरण करते हैं, वहीं साहित्यिकता, संवेग, वैदुष्य, आंचलिकता, सरसता एवं आत्मीयता की भावना सहेजे गद्य के फलक पर भी ओज-तेज अग्नि धर्मा लेखन के साथ विद्यमान हैं। वह स्वतंत्रता सेनानी के रूप में ब्रिटिश सत्ता के अन्याय, अत्याचार एवं दमन नीति के विरुद्ध शंखनाद कर जूझते हैं, वहीं संपादक के रूप में आग उगलते संपादकीय एवं लेखों के माध्यम से सम्पूर्ण समाज के मानस को उद्वेलित, प्रेरित एवं जाग्रत करते हैं। एक ओर वह लाल, बाल, पाल नाम से विख्यात त्रिरत्न लाला लाजपत राय, बालगंगाधर तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल की विचार सरिता में अवगाहन कर अंग्रेजों के विरुद्ध सतत संघर्ष की हुंकार भरते हैं तो वहीं वह स्वयं में गांधी के सत्य, प्रेम एवं अहिंसा की प्रवहमान धारा का अनुभव करते हैं। यही कारण है कि उनकी रचनाओं में एक ओर जहां ओज-तेज की प्रखरता है, शत्रु विनाश का लक्षित संधान है तो वहीं दूसरी ओर पृष्ठ-दर-पृष्ठ सत्य, शांति, सदाचार, करुणा एवं मानवता के रुचिर मार्मिक चित्र भी दृष्टव्य हैं।

समग्रता में देखें तो माखनलाल चतुर्वेदी का साहित्य प्रकृति के प्रति आत्मीयता एवं सम्पूर्ण मानव जाति के प्रति प्रेम का आख्यान है। वहां ब्रिटिश दासता से मुक्ति का आह्वान है तो सुप्त जन मानस के लिए प्रेरणा भरी ललकार भी। वह अपनी लेखनी से प्रभाती गाते हैं और उगते सूर्य की आराधना भी। वह ओजस्वी वक्ता के रूप में श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देने की कला में पारंगत हैं तभी तो गांधी उनकी वक्तृत्व कला की सराहना करते हुए कहते हैं कि हम लोग तो केवल बातचीत करते हैं, भाषण तो माखनलाल चतुर्वेदी जी करते हैं। गांधी जी हृदय से उनको मानते थे तभी तो वे उनके जन्म स्थान बाबई, होशंगाबाद पधार कर उस माटी को प्रणाम किया था जिसने देश में राष्ट्रीयता की भावना का ज्वार उठाने वाला लाल उत्पन्न किया था।

माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल, 1889 को वर्तमान मध्यप्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई ग्राम में शिक्षक पिता नंदलाल चतुर्वेदी के घर हुआ था। पिता के मार्गदर्शन में घर पर ही हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, गुजराती और अंग्रेजी भाषा का अभ्यास कर समान अधिकार प्राप्त कर केवल 16 वर्ष की अवस्था में 8 रुपए मासिक वेतन पर शिक्षक के रूप में काम करना प्रारंभ किया था। उसके एक वर्ष पूर्व 1904 में आपका विवाह हो चुका था। शिक्षक के रूप में आप बच्चों के प्रिय शिक्षक रहे। शिक्षण के साथ लेखनी भी गतिशील रही। 1908 में 'हिंद केसरी' अखबार द्वारा 'राष्ट्रीय आंदोलन एवं बहिष्कार' विषय पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपनी छाप छोड़ी। 1913 में खंडवा से 'प्रभा' मासिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ तो शिक्षक की नौकरी छोड़ संपादक के रूप में कार्य प्रारंभ किया। प्रभा पत्रिका गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप प्रेस में छपने के कारण आपका परिचय विद्यार्थी जी से हुआ और जब 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ तो विद्यार्थी जी के साथ आपकी भेंट महात्मा गांधी और कवि मैथिलीशरण गुप्त से हुई। आप गांधी विचार से प्रभावित हो उनके आंदोलनों में सहभागिता करने लगे। असहयोग एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन में आपको कारावास हुआ। इसी बीच 'कर्मवीर' समाचार पत्र का संपादन दायित्व भी संभाला। गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रख्यात पत्र 'प्रताप' का संपादन दायित्व भी तब हाथ में लिया था, जब विद्यार्थी जी को जेल में बंद कर दिया गया था। अपने लेखों में अंग्रेजी नीति के विरोध एवं जनता को आंदोलन करने हेतु प्रेरित करने वाली सामग्री छापने के कारण आपके कार्यालय अर्थात घर पर अर्धशताधिक बार छापा डाला गया। पर निर्भय स्वभाव वाले माखनलाल न डरे, न झुके बल्कि हर बार नयी ऊर्जा एवं ऊष्मा के साथ प्रकट हुए।

माखनलाल चतुर्वेदी के साहित्यिक अवदान के लिए 1943 में देव पुरस्कार, 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1959 में सागर विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट. की मानद उपाधि, 1963 में पद्मभूषण आदि सम्मान प्रदान किये गये। 1967 में संसद द्वारा राजभाषा हिंदी संशोधन बिल के विरोध में आपने पद्मभूषण अलंकरण राष्ट्रपति महोदय को वापस कर दिया था, जो आपकी हिंदी के प्रति अविचल निष्ठा एवं सेवा का जीवंत प्रमाण है। ह\मि किरीटिनी, हिम तरंगिणी, युग चारण, समर्पण, समय के पांव, साहित्य के देवता आदि प्रमुख कृतियां हैं। मां भारती का यह साहित्य साधक पुत्र 30 जनवरी, 1968 को भोपाल में इस माटी को अंतिम प्रणाम कर परलोक गमन कर गया। सरकार ने 1977 में उनकी स्मृति में 25 पैसे का एक डाक टिकट जारी कर श्रद्धांजलि अर्पित की। भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना कर उनका स्वप्न साकार किया। माखनलाल चतुर्वेदी हमारे मन-मस्तिष्क में सदैव बसे रहेंगे।

सम्मान, सम्मेलन और कविता का खोता जन-सरोकार

(जब कविता मंचों में सिमट जाए, जन-सरोकार पीछे छूट जाएँ और आत्ममुग्धता के बंद वृत्त में कवियों का लोकतंत्र तमगों व सर्टिफ़िकेटों में बदल जाए।)

- डॉ. सत्यवान सौरभ

कविता समाज की सामूहिक चेतना की आवाज़ होती है। वह समय का दस्तावेज़ भी है और समय से टकराने का साहस भी। लेकिन आज जब हम अधिकांश कवि सम्मेलनों, साहित्यिक आयोजनों और तथाकथित सांस्कृतिक मंचों को देखते हैं, तो एक असहज प्रश्न सामने खड़ा हो जाता है—क्या कविता अपने मूल उद्देश्य से भटक चुकी है?

आज का दृश्य लगभग एक जैसा है। मंच पर कवि हैं, सामने बैठे श्रोता भी अधिकांशतः कवि ही हैं। कवि एक-दूसरे को बुलाते हैं, कवि ही एक-दूसरे की किताबें ख़रीदते हैं और सम्मान भी आपस में बाँट लिए जाते हैं। आयोजक वही, अतिथि वही, निर्णायक वही और प्रशंसक भी वही। यह साहित्यिक लोकतंत्र नहीं, बल्कि एक सीमित और आत्मसंतुष्ट वृत्त बन चुका है, जिसमें आम समाज की उपस्थिति लगभग नगण्य है।

यह सवाल उठाना आवश्यक है कि कविता आखिर किसके लिए है? क्या वह केवल कवियों के लिए है, या समाज के लिए? यदि कविता का पाठक वही व्यक्ति है जो स्वयं कविता लिख रहा है, तो यह स्थिति आत्मसंवाद की है—संवाद नहीं। साहित्य का इतिहास बताता है कि जब-जब रचनात्मक अभिव्यक्ति ने अपने सामाजिक सरोकार खोए हैं, तब-तब वह धीरे-धीरे अप्रासंगिक होती चली गई है।

कविता का जन्म किसी वातानुकूलित सभागार में नहीं हुआ था। वह खेतों की मिट्टी, मज़दूर के पसीने, स्त्री की चुप्पी, दलित के अपमान, आदिवासी के विस्थापन और आम आदमी की रोज़मर्रा की पीड़ा से उपजी थी। कबीर, निराला, नागार्जुन, त्रिलोचन, पाश या मुक्तिबोध—इनकी कविता इसलिए जीवित है क्योंकि वह सत्ता से असहज प्रश्न पूछती है और समाज के हाशिये पर खड़े व्यक्ति की आवाज़ बनती है। लेकिन आज की कविता का बड़ा हिस्सा सत्ता के निकट, संस्थानों के सुरक्षित घेरे में और आपसी प्रशस्ति में उलझा हुआ दिखाई देता है। बड़े-बड़े साहित्यिक संस्थानों, अकादमियों और विश्वविद्यालयों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भरी पड़ी हैं। मुस्कुराते चेहरे, हाथों में शॉल, स्मृति-चिह्न और प्रशस्ति-पत्र। सवाल यह नहीं है कि सम्मान गलत है; सवाल यह है कि सम्मान किसे और क्यों दिया जा रहा है। क्या ये सम्मान उस रचना के लिए हैं जिसने समाज में कोई हलचल पैदा की? या फिर ये सम्मान नेटवर्किंग, पहुँच और आपसी समीकरणों का परिणाम हैं?

आज कविता भी एक तरह की 'ब्रांडिंग' का हिस्सा बनती जा रही है। कवि की पहचान उसकी कविता से कम और उसके मंचों, आयोजनों और तस्वीरों से ज़्यादा होने लगी है। यह स्थिति रचनात्मकता के लिए घातक है। जब कवि अपनी कविता से ज़्यादा अपने 'प्रेज़ेंस' पर ध्यान देने लगता है, तब कविता धीरे-धीरे आत्मप्रचार का माध्यम बन जाती है।

एक और गंभीर प्रश्न पाठक का है। आम पाठक कविता से दूर क्यों हो रहा है? इसका उत्तर केवल पाठक की अरुचि में नहीं, बल्कि कविता की बदलती प्रकृति में भी छिपा है। जब कविता आम जीवन की भाषा, पीड़ा और सवालों से कट जाती है, तब वह केवल एक बौद्धिक अभ्यास बनकर रह जाती है। परिणामस्वरूप कविता मंचों तक सिमट जाती है और समाज से उसका संवाद टूटने लगता है।

कवि का दायित्व केवल सौंदर्य रचना नहीं, बल्कि सत्य के पक्ष में खड़ा होना भी है। कविता का काम सत्ता को सहज बनाना नहीं, बल्कि उसे असहज करना है। लेकिन आज कई कवि सत्ता-समीकरणों से टकराने के बजाय उनके अनुकूल रचना करना अधिक सुरक्षित समझते हैं। यह सुरक्षा कविता की आत्मा को धीरे-धीरे खोखला कर देती है।

सम्मेलन संस्कृति पर भी गंभीर आत्ममंथन की आवश्यकता है। क्या हमें इतने अधिक कवि सम्मेलन चाहिए, या हमें कविता को समाज के बीच ले जाने के नए रास्ते खोजने चाहिए? क्या कविता केवल मंच पर पढ़े जाने की वस्तु है, या वह स्कूलों, कॉलेजों, मज़दूर बस्तियों, गाँवों और आंदोलनों तक पहुँचनी चाहिए? यदि कविता केवल चुनिंदा लोगों के बीच सीमित रह जाएगी, तो उसका सामाजिक प्रभाव शून्य हो जाएगा।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि कई बार 'सरोकार' भी एक फैशन बन जाता है। मंचों पर गरीबी, स्त्री और हाशिये की बात की जाती है, लेकिन वह बात अक्सर प्रतीकात्मक रह जाती है। वास्तविक जीवन के संघर्षों से उसका सीधा संवाद नहीं होता। कविता तब तक जीवित नहीं हो सकती, जब तक वह जोखिम उठाने को तैयार न हो—सामाजिक भी और वैचारिक भी।

कविता का संकट केवल कवियों का संकट नहीं, बल्कि समाज की सांस्कृतिक चेतना का संकट है। जब साहित्य आत्मालोचना छोड़ देता है, तब वह सजावट बन जाता है। और जब सजावट ही उद्देश्य बन जाए, तब सवाल, संघर्ष और परिवर्तन की संभावना समाप्त हो जाती है।

आज ज़रूरत है कि कवि अपने भीतर झाँकें। यह पूछें कि वे क्यों लिख रहे हैं—सम्मान के लिए, मंच के लिए, या समाज के लिए? यह आत्ममंथन असुविधाजनक हो सकता है, लेकिन आवश्यक है। क्योंकि कविता का मूल्य तालियों, प्रमाण-पत्रों या तस्वीरों से नहीं आँका जाता। उसका मूल्य इस बात से तय होता है कि वह किसके पक्ष में खड़ी है और किससे सवाल कर रही है।

अंततः, कविता का भविष्य इसी पर निर्भर करेगा कि वह आत्ममुग्ध मंचों से बाहर निकलकर फिर से जीवन की धूल में उतरने का साहस करती है या नहीं। यदि कविता समाज की धड़कन से कट गई, तो वह केवल संग्रहालय की वस्तु बनकर रह जाएगी—सुंदर, पर निष्प्राण। कविता को जीवित रखने के लिए कवि को जीवित समाज से जुड़ना होगा। यही उसका धर्म है, यही उसकी सार्थकता।

(डॉ. सत्यवान सौरभ, पीएचडी (राजनीति विज्ञान), एक कवि और सामाजिक विचारक है।)

धर्मेंद्र ने 'दुनिया भर में मशहूर माघमेला' और जोरन्दा में सत्य महिमा धर्म के उदय को दो सौ साल पूरे होने पर बधाई दी

मनोरंजन शासमल, स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेश्वर : केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 'दुनिया भर में मशहूर माघमेला' और जोरंडा में सत्य महामी धर्म के उदय को दो सौ साल पूरे होने पर बधाई दी है। इस बारे में एक सोशल मीडिया पोस्ट में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सौनवाद की पवित्र जगह और सौनव ब्राह्मणों की पूजा की पवित्र भूमि जोरंडा में 'दुनिया भर में मशहूर माघमेला' और सत्य महामी धर्म के उदय को दो सौ साल पूरे होने पर बधाई। जोरंडा माघ मेला दुनिया की भलाई के लिए आदरणीय संतों की एकता, ग्रुप प्रार्थना और लगातार धूनी का एक बड़ा जमावड़ा है। ओडिशा में बनी यह अनोखी परंपरा सौनवाद पूजा के ज़रिए पूरी दुनिया को शांति, बराबरी और इंसानियत का हमेशा रहने वाला मैसेज देती रही है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 1826 में प्रभु महामी स्वामी सबसे पहले पुरी के मंदिर में प्रकट हुए थे। वहां उन्हें 'धूलिया गोसाईं' के नाम से जाना जाता था, जो बिना किसी आसन का इस्तेमाल किए ज़मीन पर सोते थे। कपिलास पहाड़ियों की गर्मी में 24 साल की कड़ी योग साधना के बाद, उन्होंने ढेंकनाल से ओडिशा के कोने-कोने में यात्रा की और महामी धर्म का प्रचार किया। उनकी पदयात्रा ने समाज में आध्यात्मिक जागृति पैदा की।

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि महामी गोसाईं के पवित्र विचार और संत कवि भीम भोई के आदर्श, ₹जीवों के दुख को गहराई से देखूं, असंतुष्ट, भले ही मैं अपने जीवन के लिए नरक में गिर जाऊं, दुनिया का उद्धार हो जाएगा₹ आज के समाज के लिए बहुत प्रासंगिक हैं। आइए इस शुभ अवसर पर हम सभी के कल्याण का संकल्प लें। मेरा मानना है कि महामी धर्म का यह त्याग दुनिया से अंधेरा दूर करेगा और शांति की रोशनी जलाएगा।

श्री विश्वकर्मा जयंती का तेरहवां विशाल जागरण सम्पन्न

परिवहन विशेषन्यूज

हैदराबाद शमशाबाद हमीदुल्ला नगर स्थित श्री जाट समाज तेलंगाना सर्वे नंबर 49/1 के तत्वावधान विश्वकर्मा जयंती मारवाड़ी समिति हाईटेक सिटी, गच्छीबावली द्वारा विश्वकर्मा जयंती समारोह का आयोजन किया गया।

आज यहाँ गणेशाराम ढाका, रामनिवास गोरछिया, ओमप्रकाश सिंवर द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, विश्वकर्मा जयंती के तहत शुक्रवार 30 जनवरी 2026 सायं 7 बजे पूजा-अर्चना व महाप्रसादी का कार्यक्रम रखा गया। समारोह के लिए पंडाल को फूलों व लाइट से सजाया गया। ज्योत प्रज्वलन के बाद रात्रि में जागरण में राजस्थान के प्रसिद्ध भजन गायक कलाकार दिनेश नागौरी एंड पार्टी म्युजिकल ग्रुप द्वारा भजनों की प्रस्तुतियां दी। अंतरराष्ट्रीय डांसर अनु सोलंकी, मटकी डांसर मैना राजस्थानी, सुप्रसिद्ध डांसर पुजा चौधरी ने नृत्य प्रस्तुत किया। अवसर पर सर्व समाज ने अध्यक्ष व सचिव एवं अतिथियों का राजस्थानी साफा पहनाकर सम्मान किया। समाज बन्धुओं के लिए भोजन-प्रसादी की व्यवस्था कार्यक्रम स्थल पर की गयी। समस्त कार्यकारणी सदस्यगण ने समाज बन्धुओं को विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा भगवान को ब्रह्मांड का पहला वास्तुकार माना जाता है, जिन्हें महादेव के त्रिशूल, कृष्ण भगवान के सुदर्शन चक्र व अस्त्र-शस्त्र बनाने के लिए जाना जाता है। जयंती पर्व को विश्व भर में कारीगर, बढ़ई, शिल्पकार, लोहार, श्रमिक हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आयोजन में गणेशाराम ढाका, रामनिवास गोरछिया, ओमप्रकाश सिंवर, दामोदर लोछब, हनुमाननाथ सिद्ध, गोपालराम जाखड़, भंवरसिंह सिसोदिया, हुकमीचन्द्र जाट, कोजाराम नैण, रामप्रताप जाखड़, आणंद सिंह, नेमाराम सियाग झबरसिंह, सुरजाराम कुकणा, गजेन्द्र सिंह, लिखमाराम, पुनिया, मांगीलाल सिरडिया, चतरसिंह, टिकुराम सारण हजारिराम गोदारा, हनुमानराम कुम्हार, सुरेश बाडियासरा, ओमप्रकाश बाडियासरा, हुनमानराम मैंया, मुकराम सुथार व समाज बन्धुओं का विशेष सहयोग रहा। कवरेज पत्रकार रिपोर्टर मिडिया जगदीश सीरवी ने किया। विश्वकर्मा जयंती का संपूर्ण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पी एम एल सीरवी यूट्यूब चैनल द्वारा किया गया। धन्यवाद ज्ञापन व महाआरती के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

संत रविदास : नैतिक चेतना और आज का भारतीय समाज

शम्भू शरण सत्यार्थी

जब भारतीय समाज अपने लोकतांत्रिक दावों और सामाजिक यथार्थ के बीच फँसा दिखाई देता है, तब संत रविदास का स्मरण केवल अतीत की ओर देखना नहीं बल्कि वर्तमान की कठोर समीक्षा करना भी है। संत रविदास उस परंपरा के संत नहीं हैं जिन्हें केवल भक्ति के दायरे में सीमित किया जा सके। वे दलित विमर्श की उस नैतिक चेतना के प्रतिनिधि हैं जिसने जाति-आधारित असमानता को ईश्वर, धर्म और समाज—तीनों के सामने चुनौती दी।

दलित विमर्श का केंद्रीय प्रश्न आत्मसम्मान का है। संत रविदास का जीवन और विचार इसी आत्मसम्मान का उद्घोष हैं। एक ऐसे समाज में, जहाँ जन्म के आधार पर मनुष्य की हैसियत तय होती थी, रविदास ने श्रम को गरिमा और भक्ति को प्रतिरोध में बदल दिया। यह कोई छोटी बात नहीं थी। यह ब्राह्मणवादी सामाजिक संरचना के मूल तर्क पर सीधा प्रहार था।

"मन चंगा तो कठौती में गंगा" जैसी पंक्ति केवल आध्यात्मिक कथन नहीं है; यह उस धार्मिक वर्चस्व के खिलाफ घोषणापत्र है, जो पवित्रता को जाति से जोड़ता रहा है।

आज जब हम दलित विमर्श की बात करते हैं, तो यह स्वीकार करना होगा कि संवैधानिक समानता और सामाजिक समानता के बीच की खाई अभी भी गहरी है। संत रविदास इस खाई को पाटने की चेतना देते हैं। वे कहते हैं—"सबै हरि के लोग समान।" यह कथन किसी अमूर्त ईश्वर-भक्ति का नहीं, बल्कि मनुष्य-मनुष्य की समानता का साहसिक ऐलान है। आज के समय में, जब जाति नए-नए रूपों में खुद को पुनर्स्थापित कर रही है, रविदास का यह कथन और अधिक राजनीतिक हो उठता है।

संत रविदास की 'बेगमपुरा' की कल्पना को यदि आज भी केवल आध्यात्मिक स्वप्न समझा जाए, तो यह एक ऐतिहासिक भूल होगी। बेगमपुरा दरअसल दलित विमर्श की पहली सामाजिक-राजनीतिक कल्पना है—एक ऐसा समाज जहाँ भय नहीं, कर नहीं, बेगार नहीं और अपमान नहीं है। यह उस भारत की कल्पना है, जो आज भी अधूरा है।

आज जब विकास की भाषा में भी असमानता छिपी हुई है, बेगमपुरा हमें यह प्रश्न पूछने को विवश करता है—क्या हमारा लोकतंत्र वास्तव में भयमुक्त और समतामूलक है?

धर्म के सवाल पर संत रविदास दलित विमर्श को निर्णायक दिशा देते हैं। वे धर्म को सत्ता और पाखंड से अलग करते हैं। आज का समय धार्मिक उन्माद, प्रतीकों की राजनीति और दिखावटी आस्था का है। ऐसे में रविदास का धर्म-दर्शन असहज करता है, क्योंकि वह पूछता है—यदि धर्म मनुष्य को मनुष्य से छोटा-बड़ा बनाता है, तो वह धर्म नहीं, सत्ता का औजार है। दलित विमर्श के लिए यह दृष्टि अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि धर्म का इस्तेमाल सबसे अधिक दलितों को नियंत्रित करने के लिए किया गया।

राजनीतिक स्तर पर संत रविदास की विरासत का सबसे बड़ा संकट यही है कि उन्हें प्रतीक में बदल दिया गया है। मूर्तियाँ, जयंती और भाषण—लेकिन विचार गायब। दलित विमर्श की जिम्मेदारी है कि वह संत रविदास को आस्था का विषय नहीं, वैचारिक हस्तक्षेप के रूप में स्थापित करे। जब तक रविदास केवल स्मरणीय रहेंगे, अनुकरणीय नहीं, तब तक उनका दर्शन निष्प्रभावी बना रहेगा।

आज की दलित युवा पीढ़ी पहचान और अवसर के दोहरे संकट से जूझ रही है। शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में भेदभाव नए, अधिक सूक्ष्म रूपों में मौजूद है। ऐसे समय में संत रविदास का संदेश आत्मसम्मान, श्रम की गरिमा और विचार की शक्ति का संदेश है। वे सिखाते हैं कि मुक्ति केवल सत्ता परिवर्तन से नहीं आती, चेतना परिवर्तन से आती है।

अंततः, संत रविदास दलित विमर्श में केवल ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं हैं, बल्कि एक जीवित प्रश्न हैं—क्या हम समानता को केवल संवैधानिक शब्दों में स्वीकार करेंगे या सामाजिक व्यवहार में भी उतारेंगे? उनका 'बेगमपुरा' आज भी अधूरा है, और शायद इसी अधूरेपन में उसकी प्रासंगिकता निहित है। जब तक भारतीय समाज जाति से मुक्त नहीं होता, तब तक संत रविदास की वाणी हमें असहज करती रहेगी और यही किसी भी बड़े विचार की पहचान है।

शीर्षक - खो रही आनंद मुस्कान

जाति–पाति व धर्म के नाम पर लड़ाना कितना आसान,
कमजोर हुई भारत की रीढ़ खो रही ₹आनंद₹ मुस्कान ।

टूटा है आज भी संगठन उन्हीं षड्यंत्रकारी विवादों से,
मुकर जाते देशवासी सहज एक साथ चलने के वादों से,
इंसानियत शर्मसार कब मिटेंगे कलंकित लड़ाई झगड़ें,
ताक में बैठे हैं दुश्मन भावनाओं पर प्रहार करते तगड़े,
बाहर से हुआ विकास पर अंदर अव्यवस्थित सामान,
कमजोर हुई भारत की रीढ़ खो रही ₹आनंद₹ मुस्कान ।

अपना–अपना स्वार्थ आगे आता है हर मुद्दे में पहले,
उगलता है जन समुदाय शब्दों के भारी भरकम गोले,
कभी राजनीति की मार तो कभी भ्रष्टाचार अत्याचार,
सुर्खियों में होते तर्क वितर्क विरोध प्रदर्शन के समाचार,
अंत :करण में बसा दर्द का सैलाब वो ही पुरानी दास्तान,
कमजोर हुई भारत की रीढ़ खो रही ₹आनंद₹ मुस्कान ।

स्वाधीनता का रंग भी नहीं दे सका अब तक समदृष्टि,
स्वयं कुछ परित्याग करने की सोच से हिल जाती सृष्टि,
भूचाल आ जाता है फिर बस देश में ये तेरा – ये मेरा,
खो जाता फिर कहीं आक्रोश में हर नया सुखद सवेरा,
रोज मिलते यहाँ अनगिनत दिलों में दर्द के गहरे निशान,
कमजोर हुई भारत की रीढ़ खो रही ₹आनंद₹ मुस्कान ।

– मोनिका डागा "आनंद"

विकसित भारत के दृष्टिगत आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के मायने

कमलेश पांडेय

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूत स्थिति को दर्शाता है, जिसमें वैश्विक चुनौतियों के बावजूद उच्च वृद्धि दर का अनुमान है। देखा जाए तो यह बजट 2026-27 से पहले नीतिगत दिशा तय करता है और विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों पर जोर देता है। यही वजह है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में वैसे नीतिगत सुधारों पर बल दिया गया है जो आत्मनिर्भरता, रोजगार सृजन और दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा दें। कहना न होगा कि ये सभी सुझाव वैश्विक चुनौतियों के बीच लचीलेपन और संरचनात्मक परिवर्तन पर केंद्रित हैं।

जहां तक इस आर्थिक सर्वेक्षण की मुख्य विशेषताओं की बात है तो इस सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी वृद्धि 7.4% और जीवीए 7.3% का प्रथम अनुमान दिया गया है, जबकि एफ वाई (FY) 2027 के लिए 6.8-7.2% का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। वहीं, निजी उपभोग (जीडीपी का 61.5%) और निवेश (30%) प्रमुख चालक हैं, साथ ही मुद्रास्फीति अप्रैल-दिसंबर 2025 में औसतन 1.7% रही। जबकि राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष (FY) 2026 में 4.4% तक कम होने का लक्ष्य है, जो नीतिगत स्थिरता दर्शाता है।

कुल मिलाकर अर्थिक सर्वेक्षण के प्रमुख क्षेत्रीय प्रदर्शन इस प्रकार हैं- क्षेत्र - मुख्य उपलब्धियाँ

* विनिर्माण : उच्च-तकनीकी गतिविधियों का 46.3% योगदान है; जबकि मोबाइल उत्पादन में 30 गुना वृद्धि (FY15-FY25) हुई है।

* कृषि : खाद्यान्न उत्पादन 3577.3 लाख मीट्रिक टन हो चुका है; जबकि पशुपालन में 6.1% वृद्धि दर्ज की गई है।

* सेवाएँ : जीवीए में 9.3% वृद्धि (H1 FY26) हुई है; जबकि वैश्विक निर्यात में 4.3% हिस्सा हो चुका है।

* बुनियादी ढांचा : राजमार्ग 60% बढ़े हैं; जबकि विदेशी मुद्रा भंडार $701.4 अरब पर पहुंच चुका है।

इसप्रकार ये आंकड़े उत्साहित करते हैं, क्योंकि जहां विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाऐं संघर्ष कर रही हैं, वही भारतीय अर्थव्यवस्था फर्राटे भर रही है।

जहां तक आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के नीतिगत निहितार्थ की बात है तो यह सर्वेक्षण आत्मनिर्भरता, स्वदेशी और रणनीतिक लचीलेपन पर जोर देता है, जिसमें पीएलआई (PLI) योजनाओं से 12.6 लाख नौकरियाँ सृजित हुईं हैं। यह ग्रामीण रोजगार में मनरेगा के स्थान पर 'विकसित भारत-जी राम जी' मिशन और एआई (AI) तथा स्वच्छ ऊर्जा पर फोकस सुझाता है, जो रोजगार-सघन विकास को बढ़ावा देगा। कुल मिलाकर, यह उच्च वृद्धि, कम महंगाई और समावेशी नीतियों से 2047 के विकसित भारत लक्ष्य को मजबूत बनाता है।

कहना न होगा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में उन नीतिगत सुधारों पर जोर दिया गया है जो आत्मनिर्भरता, रोजगार सृजन और दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा दें। ये सुझाव वैश्विक चुनौतियों के बीच लचीलेपन और संरचनात्मक परिवर्तन पर केंद्रित हैं। यदि ग्रामीण रोजगार सुधार की दृष्टि से देखा जाए तो मनरेगा के स्थान पर 'विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम 2025' की स्थापना का सुझाव दिया गया है, जो जवाबदेही बढ़ाएगा, अवसंरचना सुधरेगी और आय सुरक्षा मजबूत करेगा। यह ग्रामीण रोजगार को विकसित भारत 2047 के अनुरूप संरेखित करेगा।

वहीं, स्वदेशी और उत्पादन रणनीति के क्षेत्र में अनुशासित स्वदेशी अपनाने, निवेश लागत कम करने, उन्नत विनिर्माण मजबूत करने और रणनीतिक अपरिहार्यता की त्रिस्तरीय रणनीति का आह्वान किया गया है। जबकि राष्ट्रीय इनपुट लागत न्यूनीकरण रणनीति के तहत संसाधनों को किफायती बनाकर निर्यात और रोजगार बढ़ेगा। वहीं, एआई (AI) और प्रौद्योगिकी पर फोकस के तहत एआई (AI) को भारत की पूँजी, ऊर्जा और बाजार की वास्तविकताओं के अनुरूप अपनाने पर जोर दिया गया है, जबकि डेटा को रणनीतिक संसाधन मानते हुए घरेलू मूल्य बनाए रखने का ढांचा सुझाया गया।

वहीं, संप्रभु एआई (AI) बनाम एप्लीकेशन्स के ट्रेड-ऑफ बैलेंस करने की सिफारिश की गई है। जबकि ऊर्जा और पर्यावरण सुधार के दृष्टिगत राष्ट्रीय न्यूक्लियर एनर्जी मिशन को ₹20,000 करोड़ आवंटन से 2047 तक 100 GW क्षमता का लक्ष्य ,निर्धारित किया गया है। जबकि सौर/पवन ट्रांजिशन के संसाधन तीव्रता पर ध्यान देने की आवश्यकता जताई गई है।

भारत-ईयू की डील से अमेरिका क्यों भड़का

राजेश श्रीवास्तव

भारत ने 27 जनवरी को यूरोपीय यूनियन के साथ एफटीए अनाउंस कर दिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर ने इस समझौते को 'मदर ऑफ ऑल डील्स' कहा है। ईयू 27 देशों का ग्रुप और दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक ब्लॉक है। वहीं भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। दोनों के साथ आने से 200 करोड़ लोगों का मार्केट बनेगा। साथ ही दुनिया की 25% जीडीपी कवर होगी। भारत-ईयू ने पिछले साल 12.5 लाख करोड़ रुपए का ट्रेड किया। एफटीए आने से भारत की बर्लिन, रोम, म्यूनिख जैसे यूरोपीय बाजारों में और यूरोप की दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे भारतीय बाजारों में पहुंच बन जाएगी। अनुमान है कि एफटीए होने से भारत-ईयू का व्यापार जल्द ही दोगुना हो जाएगा। मौजूदा वैश्विक उठापटक के बीच दुनिया अमेरिका और चीन का ऑप्शन खोज रही हैं। भारत-ईयू के बीच ये डील होने से ग्लोबल सप्लाई चेन का चेहरा बदल जाएगा। उम्मीद है कि चीन की जगह भारत तेजी से प्रोडक्शन हब बनेगा। ईयू से ट्रेड बढ़ेगा और ट्रम्प के टैरिफ को मात दी जाएगी।

भारत और यूरोपियन यूनियन (ईयू) ने मंगलवार को मदर ऑफ ऑल डील्स की घोषणा की है। इस समझौते पर दुनिया की नजर है लेकिन खासतौर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह पसंद नहीं आएगा। इसकी वजह ट्रंप प्रशासन की हालिया महीनों में भारत और यूरोप पर दबाव बनाने की कोशिश की है, जिसमें उन्होंने व्यापार को हथियार बनाया। ग्रीनलैंड के मुद्दे पर ट्रंप ने लगातार यूरोप को धमकियां दी हैं तो भारत को 50 फीसदी टैरिफ लगाकर दबाने की कोशिश है। इन दोनों दोनों पक्षों ने अब एक-दूसरे के साथ बड़ा समझौता किया है। डोनाल्ड ट्रंप जिन दो ताकतों यानी भारत और यूरोप को किनारे लगाने की कोशिश में थे, उनके बीच महत्वपूर्ण ट्रेड डील साइन होना निश्चित रूप से उन्हें चुभेगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति इसे खुली चुनौती के तौर पर देखेंगे क्योंकि भारत-अमेरिका की ट्रेड डील अटकी हुई है। दूसरी ओर ईयू ने भी अमेरिका के साथ अपनी ट्रेड डील की मंजूरी रोक दी है। ईयू और भारत ने एक तरह से ट्रंप के दबाव में ना झुकते हुए चुनौती देने का काम किया है। पिछले साल नाटो चीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को 'डैडी' उपनाम दिया था। इसके बाद ये यह ट्रंप को एक प्रभावशाली तानाशाह के रूप में पेश करने का शॉर्टहैंड बन गया है, जिसे विरोधियों और सहयोगियों दोनों को कंट्रोल करना पसंद है।

भारत-ईयू ट्रेड डील ने 'डैडी' को परेशान कर दिया है। यह परेशानी उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के बयान में साफ झलकती है, जिसमें उन्होंने यूरोप को धोखेबाज तक कह दिया है।

इंडिया-ईयू की लंबे समय से अटकी ट्रेड डील के फाइनल होने में डोनाल्ड ट्रंप के रुख को भी कुछ एक्सपर्ट अहम मान रहे हैं। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाए, जिससे संबंधों में तनाव आया। दूसरी ओर ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की कोशिश का विरोध करने पर यूरोपीय देशों के खिलाफ भी टैरिफ का सहारा लेने की कोशिश की। इससे यूरोप में अमेरिका के खिलाफ नाराजगी बढ़ी और वह भारत के करीब आया।

दिल्ली में हुई इस ट्रेड डील से भारत ने अमेरिका को मैसेज भेजा है कि है कि वह ट्रंप की धमकियों के आगे झुकेगा नहीं। भारत ने यूके, न्यूजीलैंड और ओमान के साथ जरूरी ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए भी तेजी से कदम उठाए हैं। इस डील के फायदे पर एक्सपर्ट का कहना है कि यह ट्रेड डील अगले साल ही लागू होगी, जो भारत और यूरोप दोनों के लिए फायदे का सौदा साबित होगी।

ईयू और भारत के करीब आने से अमेरिका के लिए कई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर छूट सकता है । अमेरिका और ईयू दुनिया के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर है। ग्लोबल गुड्स ट्रेड में इनकी हिस्सेदारी 30% और ग्लोबल सर्विस ट्रेड में 43% है। अभी अमेरिका ईयू का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। 2024 में दोनों के बीच 150 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार हुआ। ईयू अपना 17.3% ट्रेड अमेरिका के साथ करता है। अब ईयू के भारत से एफटीए साइन करने से अमेरिका और ईयू के व्यापार पर असर पड़ सकता है। रूस से तेल खरीदने के चलते अमेरिका ने भारत पर टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया था। इसके बाद भारत ने रूस से तेल खरीदना कम भी किया लेकिन भारत-अमेरिका के बीच कोई ट्रेड डील नहीं हो पाई। ग्लोबल थिक टैंक ओआरएफ में इकोनॉमी और ग्रोथ प्रोग्रा के डायरेक्टर सेंटर मिहिर शर्मा के मुताबिक, 'ट्रम्प ताकत का सम्मान करते हैं। यूरोप और ब्राजील के ऊपर उनका दबाव काम करता है, लेकिन चीन और रूस पर यह बेअसर है। उसी तरह भारत-ईयू ट्रेड डील ईयू को यह मानने पर मजबूर करेगी कि भारत के पास ऑप्शंस हैं और वह उन पर काम भी कर सकता है।' ओआरएफ के वाइस प्रेसिडेंट हर्ष पंत के मुताबिक, भारत-ईयू के बीच एफटीए दो बड़े इकोनॉमिक प्लेयर्स का साथ आना है। यह अमेरिका के लिए सिग्नल है कि दोनों देश अपने एजेंडा पर आगे बढ़ने को तैयार हैं। मिहिर शर्मा के मुताबिक, 'ट्रम्प के टैरिफ की वजह से भारत और ईयू दोनों को ही काफी नुकसान हो चुका है। एफटीए की वजह से अमेरिका की अहमियत एक ट्रेड पार्टनर के रूप में कम हो सकती है। सिर्फ भारत और यूरोप ही नहीं दूसरे देश भी अब इसी तरह अमेरिका का विकल्प ढूंढ रहे हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर बीजिंग 28 जनवरी को चीन यात्रा पर पहुंचे। 8 साल बाद कोई ब्रिटिश पीएम चीन की यात्रा पर गया है। उनके साथ दर्जनों ब्रिटिश बिजनेस एग्जिक्यूटिव्स भी होंगे यानी यात्रा का मकसद व्यापार ही है। बीते दिनों कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने भी ट्रम्प के टैरिफ का विरोध कर देश के लोगों से स्वदेशी सामान खरीदने की अपील की। अब वो खालिस्तान के मुद्दे पर भारत से खराब हुए रिश्तों को भी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। मार्च में कार्नी भारत दौरे पर आएंगे। तीन दिन के दौरे पर चीन गए कीर स्टारमर ने 29 जनवरी को शी जिनपिंग से मुलाकात की। अंतरराष्ट्रीय मामलों में जेएनयू के प्रोफ़ेसर स्वर्ण सिंह कहते हैं, 'इन घटनाओं ने ईयू को नाटो से इतर साझेदारियां तलाशने की इच्छा को और मजबूत किया है। इसलिए ईयू-इंडिया-एफटीए सिर्फ इकोनॉमिक स्ट्रेटजी तक सीमित न रहकर, अमेरिका के खिलाफ ईयू के लिए एक जियो-पॉलिटिकल इंश्योरेंस के रूप में सामने आता है।'

भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच 'मदर ऑफ ऑल डील्स' से अमेरिका भड़का हुआ है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि यूरोप के लिए यूक्रेन युद्ध से ज्यादा जरूरी ट्रेड है। वह अपने खिलाफ युद्ध को फंड कर रहा है। बेसेंट ने कहा कि इस डील से भारत को ज्यादा फायदा होगा।

भारत-ईयू की डील से अमेरिका इतना परेशान क्यों है, क्या वाकई भारत को इस डील से ज्यादा फयदा होगा और ट्रम्प के टैरिफ का असर घटेगा। जब दो या ज्यादा देश आपस में ये तय कर लेते हैं कि वे एक-दूसरे के सामान और सेवाओं पर टैक्स, पाबंदियां और रुकावटें कम या खत्म कर देंगे, तो उसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो एफटीए व्यापार का 'टोल फ्री हाईवे' है।

भारत ने 27 जनवरी को यूरोपीय यूनियन के साथ एफटीए अनाउंस कर दिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर ने इस समझौते को 'मदर ऑफ ऑल डील्स' कहा है। ईयू 27 देशों का ग्रुप और दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक ब्लॉक है। वहीं भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। दोनों के साथ आने से 200 करोड़ लोगों का मार्केट बनेगा। साथ ही दुनिया की 25% जीडीपी कवर होगी।

भारत-ईयू ने पिछले साल 12.5 लाख करोड़ रुपए का ट्रेड किया। एफटीए आने से भारत की बर्लिन, रोम, म्यूनिख जैसे यूरोपीय बाजारों में और यूरोप की दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे भारतीय बाजारों में पहुंच बन जाएगी। अनुमान है कि एफटीए होने से भारत-ईयू का व्यापार जल्द ही दोगुना हो जाएगा। मौजूदा वैश्विक उठापटक के बीच दुनिया अमेरिका और चीन का ऑप्शन खोज रही हैं।

भारत-ईयू के बीच ये डील होने से ग्लोबल सप्लाई चेन का चेहरा बदल जाएगा। उम्मीद है कि चीन की जगह भारत तेजी से प्रोडक्शन हब बनेगा। ईयू से ट्रेड बढ़ेगा और ट्रम्प के टैरिफ को मात दी जाएगी।

लंदन के इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की सीनियर एनालिस्ट सुमेधा दासगुप्ता के मुताबिक, 'मौजूदा हालातों की वजह से व्यापार डगमगा रहा है। ऐसे में भारत और यूरोप को भरोसेमंद ट्रेड पार्टनर की जरूरत है। भारत अमेरिकी टैरिफ के असर को कम करना चाहता है। जबकि यूरोप चीन पर निर्भरता घटाना चाहता है, जिसे वह भरोसेमंद नहीं मानता।'

नाराज अमेरिका गुस्सा जाहिर कर रहा

भारत और ईयू के बीच ट्रेड डील होने के बाद ट्रम्प सरकार के मंत्री इस डील की आलोचना कर रहे हैं। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने यूरोप के भारत के साथ ट्रेड डील करने को निराशाजनक बताया है। उन्होंने एक अमेरिकी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, 'यूरोप रूस-यूक्रेन युद्ध के फ्रंटलाइन में हैं। भारत ने रूस से सैंक्शन्ड कच्चा तेल खरीदना शुरू किया और रिफाइंड करके यूरोप को बेचने लगा। यूरोप खुद ही अपने खिलाफ चल रही जंग को फंड कर रहा है।'

बेसेंट ने कहा कि हमने भारत को रूसी तेल खरीदने से रोकने के लिए 25% टैरिफ लगाया। यूरोप ने हमारा साथ देने के बजाय, भारत से जाकर ट्रेड डील कर ली। वो व्यापार को यूक्रेन के लोगों के आगे रखते हैं। अमेरिकी ट्रेड रिप्रजेंटेटिव जैमिसन ग्रीर ने कहा है कि इस डील से भारत को ज्यादा फायदा है। उन्हें यूरोप के मार्केट में अपना सामान बेचने का ज्यादा मौका मिलेगा। ग्रीर ने यह भी संभावना जताई है कि ईयू की चेयरमैन वॉन डेर लेयेन ने यूरोप में भारतीय लेबर्स के आने-जाने पर बातचीत की है।

मोटी धनराशि व विदेशी खिलाड़ियों का आकर्षण बना कोलावीरा फुटबॉल मैच, कोल्हान रक्षा संघ हाथों उद्घाटित

अफ्रीकी देशों के खिलाड़ियों ने दिखाया अपनी हुनर

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड - झारखंड

जमशेदपुर, झारखंड के कोल्हान कमिश्नरी मे खेल के मामले मे मोटी पारितोषिक धन राशि से लैस , विदेशी खिलाड़ियों के समावेश के कारण अन्य राज्यों के खेल प्रेमियों को आकर्षित करने वाला कोलावीरा मे आयोजित शहीद तिलका मांझी ट्रॉफी 2026 का विधिवत उद्घाटन कोल्हान रक्षा संघ के अध्यक्ष डीवार जोकौं तथा पद्मश्री छूटनी महतो के हाथों हुआ । इस अवसर पर कोल्हान रक्षा संघ की तरफ से अध्यक्ष समेत उसके तमाम पदाधिकारी जहां मौजूद रहे वहीं हजारों की तदाद में लोगों ने इस मैच का प्रथम दिन के आयोजन का लुफ्त उठाया ।

शनिवार प्रातः 9:00 बजे कोल्हान रक्षा संघ को भव्य तरीके से ढोल नगाड़े , पुष्प वृष्टि कर सम्मान पूर्वक मंच पर बुलाया गया। फिर तिलका मांझी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर फुटबॉल मैच का विधिवत उद्घाटन हुआ । मंच के निकट फिल्ड मे डीबार जोंकों को पुष्पगुच्छ देकर आर के एफ एल के अधिकारी शक्ति पद सेनापति एवं अन्य लोगों ने सम्मानित किया । अध्यक्ष दीवार जोंकों के साथ छूटनी महतो को भी सम्मानित किया गया ।

कोल्हान रक्षा संघ के अध्यक्ष डीवार जोंकों ने अपने संबोधन मे तिलका मांझी पर बोलते हुए कहा वे भागलपुर के सुल्तानगंज मे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे जो देश मे सर्वप्रथम स्वतंत्रा की लड़ते शहीद हुए हैं । उन्होंने कहा भागलपुर के तत्कालीन कमिश्नर को तिलका मांझी ने तीर से मारा था । उन्होंने इन इतिहास गाथा को अगली पीढ़ी तक पहुंचने पर बल दिया , मंच पर तिरंगा आदि से लैस बच्चों की तरफ इशारा करते हुए इस बात को झारखंड सरकार के सेवानिवृत्त वरीय सचिव स्तर के अधिकारी ने खचाखच भरी खेल मैदान मे गणतंत्र दिवस के पश्चात रखा ।

इस अवसर पर कमेटी के मुख्य संरक्षक आरकेएफएल के सीपीओ शक्तिपद सेनापति, संयोजक मो अख्तर हुसैन व रविंद्र मंडल जो स्वयं भी कोल्हान रक्षा संघ के पदाधिकारी हैं आदि अनेक गणमान्य मंच पर उपस्थित थे ।इसके बाद आकर्षक रूप से मैच का आरंभ हुआ । जो जहां अफ्रिकी देशों के खिलाड़ियों ने लोगों का मन मोह लिया ।

बार इस टूर्नामेंट में दक्षिण अफ्रीका, घाना, युगांडा और आइवरी कोस्ट के खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं। टूर्नामेंट में विजेता टीम को 7 लाख व ट्रॉफी, उपविजेता को 5 लाख व ट्रॉफी, तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमों को 2.5 लाख रुपए और ट्रॉफी के अलावा बेस्ट गोलकीपर, मैन ऑफ द मैच सहित कई अन्य पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।

दिन भर चले मैच प्रतियोगिता के साथ कल टूसु पर्व का भी आयोजन रखी गयी है । जहां संस्कृति संरक्षण हेतु मोटी धनराशि पारितोषिक के तौर पर दी जायेगी ।

कानपुर में मिली वैशाली बिहार के साबिर की रक्त रंजित लाश : हत्या की आशंका, जांच शुरू

– बिहार से आकर टेनरी में मजदूरी कर परिवार का पेट पाल रहा था साबिर

सुनील बाजपेई

कानपुर। यहां आज शनिवार की सुबह जाजमऊ गंगापुल पर मिली टेनरीकर्मी की रक्तरंजित लाश ने हड़कंप मचा दिया। उसकी हत्या किए जाने की भी प्रबल आशंका का व्यक्त की गई है, जिस पर सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज घटना की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, शाबिर का शव गंगापुल के पैदल ट्रैक पर मिला। उनके सिर में गहरे घाव के निशान थे। घटनास्थल से लगभग 4 मीटर दूर रेलिंग और डिवाइडर पर खून के छींटे भी मिले हैं, जिससे पुलिस को हत्या कर शव को यहां फेंके जाने की आशंका है।

पुलिस के अनुसार मृतक मोहम्मद शाबिर (38) मूल रूप से वैशाली, बिहार के रहने वाले थे वह वर्तमान में उन्नाव के थाना गंगाघाट स्थित अखलाक नगर में किराए के मकान में अपनी पत्नी मुन्नी (32) और चार बच्चों- सुहैल (14), आलिया (9), यास्मीन (7) और अफसाना (3) के साथ रहते थे और जाजमऊ स्थित एक जूता फैक्ट्री में मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पाल रहे थे। उनके बड़े भाई मोहम्मद आबिद ने बताया कि बीती रात करीब 8 बजे उनकी शाबिर से बात हुई थी। आज शनिवार सुबह उनके एक मित्र ने उन्हें सूचना दी कि शाबिर गंगापुल पर लहूलुहान अवस्था में पड़े हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस मौत के कारणों की जांच कर रही है।

विधायक डॉ अजय गुप्ता ने श्री गुरु रविदास की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमो में पहुँच गुरु चरणों में लगवाई हाजरी

अमृतसर: 31 जनवरी (साहिल बेरी)

सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत श्री गुरु रविदास जी की 649 वीं जयंती के उपलक्ष्य पर केंद्रीय विधानसभा क्षेत्र से विधायक डॉक्टर अजय गुप्ता ने शहर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमो में पहुंच कर गुरु जी के चरणों में नतमस्तक होकर आशीर्वाद लिया तथा गुरु चरणों में सरबत के भले की अरदास की।

विधायक डॉ अजय गुप्ता ने सभी को श्री गुरु रविदास जी की जयंती पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गुरु रविदास जी ने अपने समय में गैर बराबरी पर आधारित सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था पर चोट की थी। गुरु जी के दोहे 'ऐसा चाहूं राज मैं मिले सबों को अन्न छोट बड़ सम बसें रविदास रहे प्रसन्न' का उच्चारण करते हुए विधायक डॉ गुप्ता कहा कि इस दोहे के माध्यम से गुरु रविदास जी ने सामाजिक एवं आर्थिक विषमता को मिटाकर सामाजिक एवं आर्थिक क्षमता की वकालत की।

विधायक डॉ गुप्ता ने कहा कि गुरु रविदास जी ने अपने सत्संग और कीर्तन के माध्यम से निर्गुण भक्ति करते हुए जगह-जगह घूम कर देश के दलित पीड़ित शोषित समाज को जागृत करने का काम किया। आज भी उनके जीवन और संघर्षों से प्रेरणा लेकर समाज को जागरूक करने की जरूरत है। उन्होंने सभी को गुरु जी दर्शाए मार्ग पर चलते हुए अपने गुरुओं और महापुरुषों के सपनों को पूरा करने का आह्वान किया। उन्होंने गुरु रविदास जी के जीवन और संघर्षों से प्रेरणा लेकर समाज में व्याप्त जातिवाद एवं अन्य विषमता को दूर करने की भी अपील की।

रांची पुलिस ने मादक पदार्थ सहित पांच को किया गिरफतार

सरायकेला जिले से महिला ड्रग तस्कर डोली परविन पुनः हुई गिरफ्तार

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

रांची , राजधानी के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में चूड़ी सेंटर गली बाबा अस्पताल के पास अवैध हथियार और मादक पदार्थों के साथ 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक रांची के निर्देश पर आयोजित छापेमारी में पुलिस ने हिमांशु यादव उर्फ लालू यादव के घर पर छापेमारी कर अवैध हथियार और ड्रग्स बरामद किया है.

सिटी एसपी के अनुसार शुक्रवार रात करीब 1:15 बजे सूचना मिली कि चूड़ी सेंटर गली बाबा अस्पताल के सामने हिमांशु यादव उर्फ लालू यादव के घर में कुछ अपराधी साजिश रच रहे हैं और उनके पास अवैध हथियार भी मौजूद हैं. इस सूचना पर वरीय पुलिस अधीक्षक रांची के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर रांची के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया. पुलिस उपाधीक्षक कोतवाली प्रकाश सोय के नेतृत्व में दल ने उक्त स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी की. घेराबंदी के दौरान पुलिस को अपनी ओर आते देख कुछ अपराधी भागने का प्रयास करने लगे पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 5 अपराधियों को पकड़ लिया, जबकि 2 अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए.

हिमांशु यादव उर्फ लालू यादव- पिता बिक्रम यादवअनिकेत पाठक, उम्र 20 वर्ष, पिता स्व. शंकर पाठक,निहाल पांडेय, उम्र करीब 26 वर्ष, पिता स्व. मनोज पांडेय, नी रज कुमार, उम्र करीब 20 वर्ष, पिता राम बचन यादव ,राहुल बड़ाईक, उम्र करीब 20 वर्ष, पिता शंकर बडाईएक देसी पिस्तौल जिसमें Made in USA लिखा हुआ,03 जिन्दा गोली,34 पुड़िया ब्राउन शुगर (वजन पुडिया सहित 04.00 ग्राम).मोबाईल फोन-04,नगद 40,000/ रुपये,एक स्कूटी रजि०-JH01CN-3023,एक बुलेट Jh01GH-6002

सरायकेला खरसावां जिलें भी नशा मुक्त समाज के अभियान में आदित्यपुर पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है. ब्राउन शुगर तस्करी के चर्चित मामले में संलिप्त मुख्य आरोपी डॉली परवीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. पुलिस ने इस मामले में पहले ही तीन अन्य सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. जिनके पास से 208 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई थी . सरायकेला कोर्ट मे डोली पर वारंट महिनों पूर्व निकला धुल फांक रहा था, जिस पर लंबे समय के बाद चुनाव के मद्देनजर आज अमल हुआ ।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023